बुधवार 04 फरवरी 2026 ■ मूल्य 3.00 ■ वर्ष 03 ■ अंक 320 ■ पृष्ठ 08

गौतमबुद्ध नगर

JBT

जनभावना टाइम्स

www.thejbt.com

निष्पक्ष और निर्भीक खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गौतमबुद्ध नगर, देहरादून, लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, हिसार, कैथल एवं करनाल से प्रकाशित

04 नर्सरी से कॉलेज तक, एडमिशन की युद्धभूमि | 07 विश्व चैंपियन गुकेश मई में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में खेलेंगे | 'धुरंधर: द रिवेंज' का दमदार टीजर रिलीज 08

लोकसभा: हंगामें के चलते कामकाज प्रभावित, आठ विपक्षी सांसद निलंबित

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर हंगामा होता रहा और इसके चलते सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। सुबह भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर और बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वक्तव्य को लेकर हंगामा हुआ। इसके चलते सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को सत्ता पक्ष के लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में कुछ सांसदों ने आसन (अध्यक्षीय चेयर) की ओर कागज फाड़कर फेंके। बाद में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के प्रस्ताव लाने के बाद 7 कांग्रेस और 01 माकपा सदस्य को सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसद- मणिकम टैगोर (कांग्रेस), अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (कांग्रेस), गुरजीत सिंह औलजा (कांग्रेस), हिबी ईडेन (कांग्रेस), डॉ. प्रशांत यादव राव पाडोले (कांग्रेस), दीन कुरियाकोसे (कांग्रेस), किरण कुमार रेड्डी (कांग्रेस) और एस. वेंकटेशन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)।

रिजिजू ने अपने प्रस्ताव में कहा कि इन सांसदों ने सदन और अध्यक्ष की गरिमा के प्रति गंभीर अशोभनीय आचरण किया है। इन सदस्यों ने महासचिव की मेज तथा अन्य अधिकारियों की मेज तक पहुँचकर अध्यक्ष की ओर काग़ज फेंके। अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने के पश्चात, नियम 374(2) के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया जाता है कि उपर्युक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव स्वीकृति के दौरान भी कुछ सदस्यों ने कागज फाड़ कर फेंके।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मंगलवार को एक बार फिर राहुल गांधी के वक्तव्य में पूर्वी लद्दाख का विषय आने पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष का कहना था कि लोकसभा अध्यक्ष के व्यवस्था देने के बावजूद राहुल गांधी फिर से वही मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं, विपक्ष का कहना था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल भी इसी कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी थी।

राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य की शुरुआत एक पत्रिका के एक लेख को सत्यापित करने से की। उन्होंने उसकी प्रति भी सौंपी। लेख पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित था। इसके बाद उन्होंने इससे जुड़ा विषय सदन में उठाना चाहा। राहुल के वक्तव्य पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जाहिर की।

उन्होंने कहा कि हम विपक्ष के नेता की बात सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन वे जिस विषय संदर्भ दे रहे हैं, अध्यक्ष पहले ही उसपर निर्णय दे चुके हैं। रिजिजू ने कहा कि जब किसी विषय पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका हो और वही विषय कल संदर्भित किया गया हो तो उसी विषय को फिर से परोक्ष रूप से उद्धृत नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं और उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों ने इसपर आपत्ति जाहिर की। उनका कहना था कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोल रहे हैं। वे लद्दाख से लगती भारतीय सीमा पर बात रख रहे हैं। हालांकि सत्तापक्ष की तरफ से इसपर आपत्ति जाहिर की गई। पीठासीन अधिकारी ने राहुल के स्थान पर अन्य वक्ताओं को चर्चा में भाग लेने और अपना वक्तव्य देने के लिए कहा। इसी बीच कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया।

इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही सुबह दो बार स्थगित हुई। इसके बाद दोपहर 02 बजे प्रारंभ होने के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि वे केवल इसी विषय पर अपनी बात रखें।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सुबह लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसद हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंच गए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में दोपहर 2 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई।

बंगाल के कई शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, लाखों की नकदी बरामद

कोलकाता। कोयला और बालू तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की। कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल सहित विभिन्न जगहों पर चल रही इस छापेमारी के दौरान व्यवसायी राजेश बंसल के आवास से कथित तौर पर कई लाख नकद बरामद किए गए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक, बरामद रकम के स्रोत को लेकर व्यवसायी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

जांच के दौरान दोपहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अधिकारी भी बस्तों के साथ मौके पर पहुंचे। इससे पहले सुबह करीब साढ़े छह बजे ईडी की तीन गाड़ियां कोलकाता से पश्चिम बर्दवान के जामुड़िया पहुंचीं और जामुड़िया बाजार से सटे पंजाबी मोड़ इलाके में व्यवसायी रमेश के घर पर तलाशी शुरू की गई। ईडी की कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही।

व्यवसायी राजेश बंसल के दोनों पुत्र सुमित बंसल और अमित बंसल के आवासों पर भी तलाशी ली गई। हालांकि वहां से कौन-कौन से दस्तावेज या सबूत मिले हैं, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, जामुड़िया के पंजाबी मोड़ क्षेत्र में एक हार्डवेयर की दुकान और एक गोदाम पर भी ईडी ने छापा मारा। इसके साथ ही जामुड़िया हाटतला इलाका स्थित 'बंसल हार्डवेयर' नामक दुकान में भी तलाशी अभियान जारी है।

इसी क्रम में, बुदबुद थाने के ओसी मनोरंजन मंडल के दुर्गापुर सिटी सेंटर स्थित आवास पर भी जांच एजेंसी ने छापा मारा और उनसे पूछताछ की जा रही है। ईडी ने पांडवेश्वर के नवग्राम और दुर्गापुर के एक अन्य पते पर भी तलाशी अभियान चलाया है। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

संक्षिप्त खबरें

आतंकी संबंधों को लेकर NIA-ATS ने बाराबंकी से युवक को किया गिरफ्तार

बाराबंकी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की सयुंक्त टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक संदिग्ध व्यक्ति को उठाया है। युवक पर आतंकियों से संपर्क होने का शक है। घर में तलाशी के दौरान टीम को कोई सामग्री नहीं मिली है। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने पुष्टि करते हुए बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद स्थित हिंद इंस्टीट्यूट में जांच टीम पहुंची थी। यहां से बदोसराय थाना क्षेत्र स्थित खोर एत्मादपुर गांव निवासी राम लखन को हिरासत में लिया है। वह दिल्ली में एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स कंपनी में काम करता है और अपनी कैंसर पीड़ित मां के इलाज के लिए दो दिन पहले बाराबंकी आया था। पुलिस की ओर से बताया गया कि राम लखन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। उसका 'रामलखन पासी 3628' नाम से फेसबुक अकाउंट है, जिसके करीब 6.3 हजार फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उसने एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें दो फरवरी को सीतापुर स्थित महाराजा छीता पासी के किले पर जाने का जिक्र था।

CBI ने आयकर विभाग के स्टेनोग्राफर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने चेन्नई में आयकर विभाग में तैनात एक स्टेनोग्राफर को 1.50 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उस पर 19 लाख रुपये के बकाया आयकर को समाप्त कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई के अनुसार स्टेनोग्राफर अभिनंदन सिंह ने आकलन वर्ष 2020-21 के तहत लंबित 19 लाख रुपये के आयकर बकाये को शून्य कराने के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत रिश्वत के रूप में मांगा था। इस संबंध में 02 फरवरी को शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। एजेंसी ने जाल बिछाकर शिकायतकर्ता से 1.50 लाख रुपये की अवैध राशि स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी रकम स्टेनोग्राफर के कब्जे से बरामद की गई। सीबीआई ने उसके आवासीय परिसर की तलाशी भी ली, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अभिनंदन सिंह को आज चेन्नई की सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

असम में भारत-किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास चार से

गुवाहाटी। भारत और किर्गिस्तान दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए 4 से 17 फरवरी तक असम में एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास होने जा रहा है। इसकी जानकारी मंगलवार को सेना के अधिकारियों ने दी है। इस संयुक्त अभ्यास का 13वां एडिशन, जिसका नाम एक्सरसाइज खंजर है, असम के मिसामारी में होगा। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी स्थितियों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका मकसद समन्वय, सामरिक कौशल और ऑपरेशनल तैयारी में सुधार करना है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा और भारत और किर्गिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को मजबूती प्रदान करेगा। दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेज के बीच तालमेल बढ़ाना इस अभ्यास का एक मुख्य उद्देश्य है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संयुक्त प्रशिक्षण में सबसे अच्छे तरीकों और ऑपरेशनल अनुभवों को साझा किया जाएगा, खासकर शांति स्थापना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य अभियानों में जटिल शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी माहौल से निपटने में।

वाई खेमचंद सिंह मणिपुर में भाजपा के विधायक दल के नेता चुने गए

नई दिल्ली। मणिपुर में वाई. खेमचंद सिंह को मंगलवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही, पूर्वोत्तर राज्य में उनके नेतृत्व में सरकार गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी घटक दलों के विधायकों की बैठक मंगलवार रात को होगी, जिसमें सिंह के नाम को राजग विधायक दल के नेता के रूप में अनुमोदित किये जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, सिंह को मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में इस पद के लिए चुना गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के अलावा, बैठक में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ और पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। वर्तमान में, मणिपुर में भाजपा के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के 32 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी।

जनता दल (यूनाइटेड) ने छह सीटें जीती थीं, जिनमें से पांच विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए। अन्य विधायकों में से छह नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) से, पांच नागा पीपुल्स फ्रंट से, पांच कांग्रेस से, दो कुकी पीपुल्स अलायंस से, एक जद (यू) से और तीन निर्दलीय हैं। एक मौजूदा विधायक का निधन हो जाने के कारण वर्तमान में एक सीट रिक्त है।

फैसले में देरी एक चिह्नित बीमारी, इसे खत्म किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समय पर न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता रेखांकित करते हुए मंगलवार को कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा महीनों तक फैसलों को सार्वजनिक किए बिना सुरक्षित रखे जाने की प्रथा 'एक चिह्नित बीमारी' है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल चार दिसंबर को एक याचिका खारिज करते हुए मौखिक रूप से फैसला सुनाया था और वह फैसला अब तक अपलोड नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह के आखिर तक वकील को पूरा फ़ैसला उपलब्ध कराया जाए। देरी का ज़िक्र करते हुए, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐसा लगता है कि सिर्फ़ जुबानी जमा खर्च किया जा रहा है... कोई संदेश जाना चाहिए। यह कानून की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मोटे तौर पर दो तरह के न्यायाधीश होते हैं। उन्होंने कहा कि एक मेहनती न्यायाधीश होते हैं, जो सबकी बात सुनते हैं और 10-15 मामलों में भी फैसला सुरक्षित रख लेते हैं। कुछ न्यायाधीश ऐसे होते हैं, जो इसके बाद फैसले नहीं सुनाते। हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। यह न्यायपालिका के सामने एक चुनौती है और यह एक पहचानी हुई बीमारी है। इसका इलाज होना चाहिए और इसे खत्म किया जाना चाहिए और इसे फैलने नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि एक और आम चलन है कि कुछ मामलों में दलीलें सुनी जाती हैं तथा फिर उन्हें आगे के निर्देशों के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाता है।

उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ अपनी आगामी बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम अन्य मुद्दों के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। हम कोई ऐसा समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे इस तरह के टाले जा सकने वाले मुकदमे खत्म हो जाएं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर अपने 15 साल के करियर में मैंने कभी भी कोई फैसला सुरक्षित नहीं रखा और तीन महीने में फैसला नहीं सुनाया। पीठ ने अपने आदेश में मामले के तथ्यों का ज़िक्र करते हुए कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर, 2025 को फैसला सुनाया था, जिसमें रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। फैसला अभी तक अपलोड नहीं किया गया है।

हमने उच्च न्यायालय की तरफ से पेश वकील को बताया है कि इस देरी का कोई कारण नहीं है। अगले हफ्ते के आखिर तक वकील को पूरा फैसला दे दिया जाए। मामला अब 16 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। नवंबर 2025 में, शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों का घटनाक्रम संबंधी विवरण सौंपने का निर्देश दिया था, जिसमें फैसले सुरक्षित रखने, सुनाने और अपलोड करने की तारीखें शामिल हों। शीर्ष अदालत अपने इस निर्देश के पालन की निगरानी कर रही है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि फैसलों की सभी प्रमाणित प्रतियों में संबंधित तीनों तारीखें साफ-साफ दर्ज हों।

भारत ने हासिल की एयर टु एयर मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक

लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मिलेगी मदद

नई दिल्ली। भारत ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की मारक दूरी बढ़ाने की तकनीक हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) का परीक्षण किया, जो पूरी तरह सफल रहा है।

स्वदेशी रूप से विकसित यह तकनीक भारत को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित करने में मदद करेगी। डीआरडीओ के मुताबिक सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) प्रणोदन आधारित मिसाइल प्रणाली का परीक्षण पूरी तरह सफल रहा है। ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) से किये गए परीक्षण में इस्तेमाल की गई जटिल मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। आईटीआर में तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे कई रेंज इंस्ट्रूमेंट्स ने इस प्रणाली के सफल प्रदर्शन को पुष्ट किया। एसएफडीआर को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं जैसे हैदराबाद की अनुसंधान केंद्र इमारत और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया गया है। डीआरडीओ ने सफल प्रदर्शन करके भारत को एयरोस्पेस की दुनिया में बढ़त दिलाई है।

इस प्रदर्शन ने भारत को उन खास देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिनके पास यह तकनीक है, जिससे दुश्मनों पर सामरिक बढ़त पाने के लिए लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। डीआरडीओ के मुताबिक नोजल-लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर समेत सभी प्रणालियों ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। लॉन्च की निगरानी डीआरडीओ की अलग-अलग प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने की।

रक्षा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने वाला पहला देश है, जो ध्वनि की गति से आठ गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है और वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी में एक गेम-चेंजर है, जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। भारत के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो गति, सीमा, सटीकता और पता लगाने की क्षमता के मामले में गेम-चेंजर है, जिससे सशस्त्र बलों को बढ़त हासिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस तकनीक के सफल प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ और इंडस्ट्री को बधाई दी। रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने सफल फ्लाइट टेस्ट में शामिल सभी टीमों को बधाई दी।

महिला 'गिग' कामगारों का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर मंगलवार को 100 से अधिक 'गिग' कामगारों ने कर्मचारी के रूप में मान्यता की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि डिजिटल मंचों पर मनमाने ढंग से खाते ब्लॉक किए जा रहे हैं, कमाई कम हो रही है और बुनियादी श्रम सुरक्षा का अभाव है। प्रदर्शन में अधिकतर महिलाएं थीं।

गिग कामगार 'जोमैटो', 'स्वीगी' जैसी सेवा प्रदाता कंपनी में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी हैं। यह प्रदर्शन 'गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन' (जीपीएसआईडब्ल्यूयू) द्वारा किया गया, जो महिलाओं के नेतृत्व वाला संगठन है। संगठन ने कहा कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाबी बाग में घरेलू सेवा मुहैया कराने वाली एक कंपनी में काम करने वालीं सुनीता ने बताया कि प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उनकी दैनिक आय में लगभग 900 रुपये का नुकसान हो चुका है। सुनीता ने बताया कि काम के घंटे और स्थिर कमाई के वादे की वजह से वह इस काम के प्रति आकर्षित हुई थीं लेकिन अब उन्हें लगातार अपना खाता ब्लॉक होने का डर सताता रहता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि शुरुआत में बहुत बुकिंग आती थीं। कंपनी के लोगों ने कहा था कि मैं अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकती हूं। अब बिना किसी स्पष्टीकरण के मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई है।

बजट में है राजधानी की सभी समस्याओं को हल करने पर फोकस : सांसद बिधूड़ी

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने 2026-27 के आम बजट को दिल्ली की सभी समस्याओं को हल करने वाला बताया।

रामवीर सिंह बिधूड़ी ने मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2026-27 के आम बजट में दिल्ली के परिवहन, पीने के पानी, स्वास्थ्य, प्रदूषण और कानून-व्यवस्था पर खास ध्यान दिया गया है। इनसे दिल्ली की जनता का जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि नई योजनाओं से रोजगार और विकास के रास्ते भी खुलेंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि पूरे देश में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का 6 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें से 27328 करोड़ की योजनाएं केवल दिल्ली के लिए ही हैं। इनमें शिवमूर्ति से महिपालपुर तक टनल और एम्स से महिपालपुर तक एलिवेटिड रोड शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं में 3500 और 5000 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा पंजाबी बाग से टीकरी बॉर्डर तक बनाए जाने वाले रोड पर 1504 करोड़, आश्रम से बदरपुर तक बनने वाली रोड पर 513 करोड़ और महरौली से दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर तक बनने वाली रोड पर 1461 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड यानी यूईआर से जुड़ने वाली सड़कों पर भी 15000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के बजट में रेलवे ने दिल्ली के लिए 2711 करोड़ का प्रावधान किया।

2009 से 2014 के बीच दिल्ली को रेलवे औसतन 96 करोड़ की योजनाएं ही देता रहा है। अब 28 गुना ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इस समय दिल्ली में 8976 करोड़ रुपये की रेलवे की योजनाओं पर काम हो रहा है जिसमें 13 स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। इस समय दिल्ली से 14 वन्देभारत ट्रेन और 8 अमृत भारत ट्रेन चल रही हैं। दिल्ली में अब रेलवे का पूरी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और नए 14 फ्लाई ओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि बजट में दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है। दिल्ली से वाराणसी तक का सफर 3.5 घंटे में पूरा करेगी। रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को इस बार 2,200 करोड़ रुपये का बजट मिला है।

देशभर में मेट्रो विस्तार के लिए 28695 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से दिल्ली मेट्रो को भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1,091 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अभी 237 करोड़ रुपये अधिक रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पांच प्रमुख अस्पतालों एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग, कलावती सरन को लगभग 10,122 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 1,185 करोड़ रुपये अधिक है। इससे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक मरीजों की देखभाल बेहतर हो पाएगी। अकेले एम्स को ही 5,500 करोड़ रुपये से अधिक मिले हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस को हाई टेक बनाने के लिए इस बार 12,846 करोड़ 13 लाख रुपये दिए गए हैं। यह पिछले वर्ष से 307 करोड़ 13 लाख रुपये अधिक है। इसके अलावा दिल्ली में जल आपूर्ति सुधारने के लिए चंद्रावल वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट को केंद्र से 380 करोड़ की सहायता राशि दी जाएगी।

भाजपा सांसद ने कहा कि बजट में दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन का बजट 5 करोड़ 78 लाख रुपये, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के लिए 470 करोड़ रुपये, राजघाट समाधि समिति और कैंटीन के लिए आठ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इग्नू विश्वविद्यालय और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर को पिछले साल के मुकाबले 10-10 करोड़ ज्यादा दिए गए हैं। 1984 सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने के मद में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं में भी दिल्ली को बड़ी हिस्सेदारी मिलने वाली है। पिछले वर्ष यह 12,483 करोड़ था, अब 13,611 करोड़ रुपये किया गया है। इस दौरान दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर और कार्यालय मंत्री बृजेश राय भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व मंच पर प्रभावी भूमिका निभा रहा है : गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर एक प्रभावी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज संसद भवन में आयोजित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक में भारत-अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए प्रधानमंत्री का भव्य अभिनंदन किया गया। यह समझौता दूरदर्शी कूटनीति और भारत की सशक्त अंतरराष्ट्रीय छवि का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य को नई अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने तथा भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह एक युगांतकारी पहल सिद्ध होगी। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत-अमेरिका के बीच बनी नई सहमति भारत की वैश्विक भूमिका को और अधिक सशक्त करने वाली है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज विश्व मंच पर भरोसे, स्थिरता और अवसर का केंद्र बन रहा है। इस साझेदारी से युवाओं के लिए रोजगार, तकनीक और नवाचार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं प्रभावी कूटनीतिक प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत–अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कह कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई वार्ता के बाद भारत पर लागू अतिरिक्त शुल्क को घटाकर 18 फीसद किया गया है। यह निर्णय भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देगा तथा वैश्विक मंच पर भारत की सुदृढ़ होती आर्थिक स्थिति और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।

मंत्री कपिल मिश्रा ने जालंधर में दर्ज एफआईआर को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने पंजाब के जालंधर में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष अवगत कराया है कि पंजाब में इकबाल सिंह द्वारा की गई शिकायत तथा उसके आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर सहित की गई कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 361ए के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण की अवहेलना है और यह विधानसभा के विशेषाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। मंत्री ने अपने पत्र में कहा कि विधानसभा की कार्यवाही के "पर्याप्त रूप से सत्य" विवरण के प्रकाशन के संबंध में आपराधिक कार्यवाही आरंभ किया जाना विधायिका की गरिमा, स्वतंत्रता एवं अधिकार में हस्तक्षेप के समान है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लेकर विशेषाधिकार समिति को संदर्भित करने का अनुरोध किया है, ताकि समुचित जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अपने पत्र में मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 361ए का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के पर्याप्त रूप से सत्य विवरण के प्रकाशन के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, जब तक यह सिद्ध न हो कि उक्त प्रकाशन दुर्भावना से किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि उक्त अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह संवैधानिक संरक्षण संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की गुप्त बैठकों की कार्यवाही से संबंधित रिपोर्टों के प्रकाशन पर लागू नहीं होता। मिश्रा ने पत्र में स्मरण कराया कि 6 जनवरी 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष आतिशी द्वारा सिख गुरुओं के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इसके पश्चात 9 जनवरी 2026 को मुख्य सचेतक अभय वर्मा द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि जालंधर पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने विधानसभा कार्यवाही का एक कथित रूप से संपादित (डॉक्टर्ड) वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है।

दिल्लीं में एक दर्जन से अधिक जगहों पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मंगलवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई राजधानी में 17 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच हवा की गति कम होने के चलते वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही रहने की संभावना है। मंगलवार को यह सोमवार की अपेक्षा अधिक दर्ज की गई। सीपीसीबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 272 दर्ज किया गया जबकि सोमवार को यह इसी समय 210 दर्ज किया गया। दिल्ली के लोगों को इस बार जाड़े के मौसम में पहले से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। प्रदूषण के स्त्रोतों के बढ़ने, हवा की गति कम होने के कारण वायु गुणवत्ता में काफी कमी दर्ज की गई। दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 256 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 19 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में, 10 केंद्रों पर 'बहुत खराब' और 10 केंद्रों पर 'मध्यम' श्रेणी में थी। हालांकि शाम को यह काफी बढ़ गई। मानकों के मुताबिक हवा में पीएम 10 का स्तर 100 से और पीएम 2.5 का स्तर 60 से नीचे होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। सीपीसीबी के मुताबिक मंगलवार की शाम चार बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 और पीएम 2.5 का औसत स्तर सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।

डीयू के तीन दिवसीय साहित्य महोत्सव में पहुंचेंगे अनेकों विख्यात चेहरे : अनूप लाठर

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव को लेकर तैयारियां जारी है। इस महोत्सव का आयोजन 12 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में 50 से अधिक वक्ता पहुंचने की उम्मीद है, साथ ही लाखों विद्यार्थियों की भी भागीदारी महोत्सव में रहेगी। यह जानकारी साहित्य महोत्सव की कोर कमेटी के उपाध्यक्ष और कन्वीनर अनूप लाठर ने दी। अनूप लाठर ने बताया कि डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह के निर्देशानुसार इस साहित्य महोत्सव का केंद्र बिन्दु राष्ट्र प्रथम होगा। विभिन्न कमेटियों से तैयारियों को लेकर बैठकें की गई हैं। सभी कमेटियों अपनी जिम्मेदारियों के

अनुसार काम कर रही हैं। इस तीन दिवसीय साहित्य महोत्सव में विख्यात लेखकों, मीडिया जगत के लोगों और जाने-माने साहित्यकारों सहित करीब 50 प्रतिभागियों ने अभी तक अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि वक्ताओं के रूप में राम माधव, विजय चौथाईवाले, फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी, रजत शर्मा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एजुकेटर खान सर, अंजना ओम कश्यप, रुबिका लियाकत, प्रफुल्ल केतकर, इंडियन हिस्ट्री उदय एस. कुलकर्णी, एक्टर और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट दिनेश मोहन, सुधांशु त्रिवेदी, विवेक रंजन अग्निहोत्री, आभास मालदहियार, अमिताभ अग्निहोत्री, राहुल शिवशंकर, दिशा अहलूवालिया जैसे कई पैनलिस्ट अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव के तीनों दिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा जिसमें पहले दिन कवि सम्मेलन, दूसरे दिन भजन क्लबिंग और तीसरे दिन विभिन्न प्रदेशों के आदिवासी और लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान पुस्तक विमोचन और पुस्तक चर्चाओं का भी आयोजन किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली: गुलाबी बाग में बंद कमरे से व्यक्ति का शव बरामद

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग स्थित एक पार्किंग क्षेत्र में बंद कमरे से 39 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया। यह व्यक्ति 25 जनवरी से लापता था। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है और उसके सिर और गर्दन पर चोट के निशान है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को उसे घटना के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची जहां उसे शव मिला। अधिकारी ने कहा, व्यक्ति 25 जनवरी से अपने घर से लापता था। 28 जनवरी को पहाड़गंज पुलिस थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।₹ पुलिस ने बताया कि गुलाबी बाग पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

तोड़फोड़ करने पर जेएनयू ने पांच विद्यार्थियों को निलंबित किया

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने पांच पीएचडी विद्यार्थियों को दो सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया है, जिनमें जेएनयू छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के चार पदाधिकारी शामिल हैं। इन विद्यार्थियों को 21 नवंबर, 2025 को डॉ. बी. आर. आंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय में प्रवेश द्वार पर लगे 'चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी' (एफआरटी) उपकरण में तोड़फोड़ करने का दोषी पाया गया था। निलंबन पत्र के अनुसार, किझाकूट गोपिका बाबू, अदिति मिश्रा, सुनील यादव, दानिश अली और नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से पूरे परिसर में 'प्रतिबंधित' कर दिया गया है और उन पर 20,000-20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। संपर्क करने पर जेएनयू प्रशासन ने इन विद्यार्थियों को निलंबन पत्र जारी किये जाने की पुष्टि की। लेकिन इस पत्र पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया।

खड़े ट्रक से एसयूवी की टक्कर, महिला की मौत, दो घायल

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर एक एसयूवी के एक खड़े ट्रक से टकराने से 23 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में सोमवार को तड़के 3.48 बजे पीसीआर पर जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि तीनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य दो का इलाज किया जा रहा है।

वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 17 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम और पेड टास्क का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को उत्तर पश्चिम जिले की साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान 25 वर्षीय पठान उजेफ खलील खान के रूप में हुई है, जो महाराष्ट्र के जालना जिले का रहने वाला है। पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर जालना से दिल्ली ला रही है।

उत्तरपश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के त्रिनगर, केशवपुरम निवासी राहुल सैनी ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे घर बैठे काम दिलाने के नाम पर 17,16,777 रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। शिकायत के आधार पर ई-एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस उपायुक्त के अनुसार जांच में सामने आया कि आरोपित साइबर अपराधियों के उस नेटवर्क का हिस्सा था, जो ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों में घुमाकर निकालने का काम करता था। पुलिस ने मनी ट्रेल और डिजिटल फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया तो पता चला कि ठगी की रकम आरोपित के खाते में आई और बाद में सेल्फ चेक के जरिए निकाली गई। तकनीकी और लोकेशन विश्लेषण के बाद पुलिस टीम आरोपित तक पहुंचने में सफल रही।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपित ने कबूल किया कि पैसों की जरूरत और ऐशो-आराम की जिंदगी के चलते वह साइबर ठगों के संपर्क में आया। गिरोह के सदस्य पहले पीड़ितों को वर्क फ्रॉम होम के नाम पर झांसे में लेते थे और फिर म्यूल अकाउंट्स के जरिए रकम ट्रांसफर कराई जाती थी। पहचान छिपाने के लिए आरोपित बार-बार मोबाइल नंबर बदलता रहता था। आरोपित की प्रोफाइल के मुताबिक वह 12वीं तक पढ़ा है और फिलहाल एक निजी होटल में शेफ के तौर पर काम करता था। पुलिस ने उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपित की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है और उसके अन्य साथियों व इसी तरह की ठगी के मामलों में संलिप्तता का भी पता लगाया जा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय का मेट्रो केबल चोरी के आरोपी 'गिग वर्कर' को जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मेट्रो लाइन से 32 मीटर तांबे का तार चुराने के आरोपी एक 'गिग वर्कर' को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उसने जनता के जीवन से खिलवाड़ किया और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि आरोपी ने केवल कुछ मूर्खतापूर्ण हरकतें ही नहीं कीं, बल्कि उसके कार्यों ने जनता के जीवन और संपत्ति को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया। जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है। न्यायालय ने 31 जनवरी को दिए आदेश में कहा, जमानत देते समय इस न्यायालय को सार्वजनिक हित और निजी हित के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। याचिकाकर्ता आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करने का दोषी है। न्यायालय ने कहा, इस मामले में आवेदक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, खासकर इसलिए क्योंकि आवेदक ने सभी के जीवन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। इसने कहा, आवेदक किसी मूर्खतापूर्ण हरकत का दोषी मात्र नहीं है, बल्कि उसने निस्संदेह सार्वजनिक खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।

दिल्ली पुलिस ने चोरी के तीन मामले को सुलझाया, दो शातिर चोर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली के साउथ-वेस्ट जिला पुलिस के किशनगढ़ थाना स्टाफ ने वाहन चोरी की वारदातों में शामिल दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के जरिए पुलिस ने दोनों आरोपियों पर शिकंजा कसा है। आरोपियों के कब्जे से चेरी के तीन एलॉय व्हील टायर सहित एलॉय व्हील खोलने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार और वारदात में प्रयुक्त हुंडई ऑरा कार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित (37) और केतन टोकस के रूप में हुई। दोनों आरोपी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे।

दरअसल, 29 जनवरी को थाना किशनगढ़ में ऑनलाइन ई-एफआईआर संख्या 80008769/26, धारा 303(2)/317(2)/3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता वी कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके हुंडई ऑरा कार से पार्किंग के दौरान अज्ञात चोर एलॉय व्हील और टायर चोरी कर ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। घटना स्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की गई, जिसमें 28 जनवरी को शाम करीब 5:30 बजे दो से तीन संदिग्ध युवक शिकायतकर्ता की कार के आसपास घूमते हुए नजर आए। फुटेज के विश्लेषण में एक हुंडई कार को संदिग्ध वाहन के रूप में चिन्हित किया गया। जांच में सामने आया कि संदिग्ध वाहन आरोपी अंकित के नाम पर पंजीकृत है। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों की गतिविधियों को लाजपत नगर, महिपालपुर और किशनगढ़ इलाकों में ट्रेस किया। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी अंकित को वाहन समेत गिरफ्तार कर लिया। लगातार पूछताछ के दौरान अंकित ने चोरी की वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर तीन चोरी किए गए एलॉय व्हील टायर सहित बरामद किए गए। आगे की पूछताछ में उसके साथी केतन टोकस को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एलॉय व्हील खोलने और नट ढीले करने में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार बरामद हुए। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसआई धर्मेंद्र, हेड कांस्टेबल योगेश, हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल संजीव और कांस्टेबल धर्मेंद्र की एक विशेष टीम गठित की गई थी। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर अजय कुमार यादव, एसएचओ किशनगढ़ की निगरानी में और मेल्विन वर्गीस, आईपीएस, एसीपी सफदरजंग एन्क्लेव के मार्गदर्शन में की गई। प

ुलिस के अनुसार, आरोपी अंकित पहले ड्राइवर के रूप में काम करता था और बाद में रैपिडो पर हुंडई ऑरा कार चलाने लगा। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और चोरी से प्राप्त पैसों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के लिए करते थे।

दिल्ली सरकार बना रही यमुना नदी पर नए पुल निर्माण की योजना

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वी हिस्सों के संपर्क में सुधार करने और यातायात जाम की समस्या को कम करने के मकसद से सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना नदी पर एक नए पुल के निर्माण या पुराने लोहे के पुल को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव ट्रांस-यमुना बोर्ड द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान रखा गया था और योजना अभी प्रारंभिक चरण में है, जिसपर पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ट्रांस-यमुना क्षेत्र में संपर्क में सुधार लाने और उत्तर-पूर्वी, उत्तरी तथा मध्य दिल्ली के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए इस पर विचार कर रही है।" अधिकारियों के अनुसार, 'रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) स्टेशन और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के तैयार होने के साथ रिंग रोड पर खास कर सराय काले खां के पास जाम बढ़ने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे फिलहाल रिंग रोड पर सराय काले खां के पास समाप्त होते हैं। जल्द ही दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी-सोहना (जेवार) लिंक भी शुरू होने वाला है। यहां एक अधिकारी ने कहा, "इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार एक नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव देने की योजना बना रही है। स्थान अभी तय नहीं हुआ है और इसपर विचार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी पुराने वज़ीराबाद से कालिंदी कुंज तक के क्षेत्र का अध्ययन करके व्यवहार्यता का पता लगाएगी। लोहा पुल (लोहे का पुराना पुल) के निचले भाग में वाहनों और ऊपरी हिस्से पर ट्रेन की आवाजाही होती है। वर्तमान में यमुना नदी पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग के लिए लगभग 25 पुल हैं।

संक्षिप्त खबरें

सनातन सेवा संस्थान ट्रस्टका पद-प्रदान कार्यक्रम संपन्न

नोएडा। सनातन सेवा संस्थान ट्रस्ट ने समाज सेवा और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पद-प्रदान कार्यक्रम सेक्टर-122 स्थित रेडियंट ब्लू होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आचार्य अवनीश महाराज ने की। उन्होंने कहा कि सेवा भाव से किया गया संगठित कार्य ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाता है। महासचिव अंकित यादव, संगठन अध्यक्ष बिजेंद्र यादव सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। ट्रस्ट ने भविष्य में गौ-सेवा, अन्नदान और शिक्षा सहायता जैसे कार्यों को विस्तार देने की घोषणा की।

8 फरवरी को होगा विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन

नोएडा। सेक्टर-19, 20 और 26 के संयुक्त तत्वावधान में 8 फरवरी को सेक्टर-19 के बरातघर में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सम्मेलन में गौतम खट्टर, राष्ट्रीय संत 1008 महामंडलेश्वर स्वामी पद्मनारायणाचार्य महाराज और महानगर प्रचारक सुमित जी मुख्य वक्ता होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होगी। सम्मेलन में बच्चे सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे। समापन श्रीराम स्तुति से किया जाएगा। समापन पर प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। इससे पहले प्रभात फेरियां भी निकाली गईं।

ग्रेटर नोएडा के भगवत शर्मा को मिला सम्मान

ग्रेटर नोएडा। एंबिशस कॉन्क्लेव फाउंडेशन के तत्वावधान में दिल्ली में आयोजित सांस्कृतिक समारोह के दौरान ग्रेटर नोएडा के भगवत शर्मा को सम्मानित किया गया। साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए स्मृति चिह्न और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया। भगवत शर्मा ने अपनी प्रेरणादायक घटना साझा की, जिसमें उन्होंने दक्षिण कोरिया की कंपनी देवू मोटर में प्रशिक्षण के दौरान पाए डॉलर से भरे पर्स को पूरी ईमानदारी से प्रशासन विभाग को सौंपा और इसके लिए ऑनेस्टी अवॉर्ड से सम्मानित हुए।

पार्क में युवक का शव पेड़ से लटका मिला

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के चिपियाना गांव के समीप पार्क में पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। पुलिस का कहना है कि युवक ने खुदकुशी की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूलरूप से गांव झबरी, जिला सीतापुर का रहने वाला 24 वर्षीय रुचित कुमार चिपियाना गांव में परिवार के साथ रहता था। रुचित यहां परिवार के साथ मजदूरी करता था। सोमवार की

सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने पार्क में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान की। शव की पहचान रुचित के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल के पास शराब की खाली बोतल और नमकीन का पैकेट आदि सामान मिला है। आशंका है कि शराब के सेवन के बाद युवक ने आत्महत्या की है। हालांकि, घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक परिजन शव लेकर अपने गांव चले गए। इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। परिजनों की शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी।

नोएडा डिपो को दो और डबल डेकर बसें मिलीं

नोएडा। मोरना स्थित नोएडा डिपो को दो और डबल डेकर बसें मिल गईं। अब इनकी संख्या बढ़कर तीन हो गई है। अधिकारियों के अनुसार होली के बाद डबल डेकर बसों की सेवा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि एक डबल डेकर बस पहले मिली थी। अब दो बसें मिली हैं। बसें स्विच मोबिलिटी कंपनी की हैं। उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें बसों को चलाने को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बसें मार्च में चलनी शुरू हो जाएंगी। बसों के रूट दो से तीन दिन में निर्धारित कर लिए जाएंगे। बसों की सुविधा को उन सभी स्थानों से जोड़ा जाएगा, जहां से अधिक यात्री मिल सकें। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को भी बस की सुविधा देने की योजना है।

बदसलूकी का विरोध करने पर हमला

रबूपुरा। फलेदा गांव निवासी मुकेश का आरोप है कि उसके भाई की पत्नी शिवाका शुक्रवार दोपहर अपने परिवार के ही दुष्यंत और दक्ष के साथ भैंस लेकर जा रही थी। रास्ते में गांव के ही राजू, लखन, सुभाष और एक अन्य व्यक्ति ने बेवजह उन्हें गाली देनी शुरू कर दी। आरोप है कि चारों ने विरोध करने पर उनके ऊपर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देकी फरार हो गए। घटना में महिला समेत तीनों लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घरों के बाहर खड़ी छह बाइक चोरी, केस दर्ज

नोएडा। सेक्टर-81 के शिवशक्ति अपार्टमेंट निवासी आकाश की बाइक 28 जनवरी को घर के पास से चोरी हो गई। सेक्टर-70 से महमूद आलम, सेक्टर-65 से रमिंद्रर सिंह और सेक्टर-121 स्थित क्लियो काउंटी सोसायटी से डिलीवरी ब्वॉय शैलेंद्र सिंह की बाइक चोरी हो गई। गिझोड़ गांव से नेहा के भाई रोहन और बिशनपुरा गांव से नितेश कुमार की बाइक चोरी हो गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

संदिग्ध के कब्जे से अवैध शराब बरामद

नोएडा। सेक्टर-24 थाने की पुलिस ने जांच के दौरान सेक्टर-54 लाल बत्ती के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से 105 पव्वे अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी की पहचान चौड़ा गांव निवासी संजीव के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ठेके बंद होने पर महंगे दाम पर शराब बेचता है। पुलिस उसके बारे में और जानकारी जुटा रही है। गांजा बेचते तस्कर को दबोचा नोएडा, 03 फरवरी (वेब वार्ता)। सेक्टर-63 थाने की पुलिस ने बहलोलपुर अंडरपास के पास से एक संदिग्ध को एक किलो 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। उसकी पहचान बहलोलपुर गांव निवासी सतपाल उर्फ सत्ते यादव के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला है कि सतपाल दिल्ली के व्यक्ति से गांजा खरीदता। इसके बाद गांजे की पुड़िया बनाकर लोगों को खपाता।

आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ग्रेनो प्राधिकरण की खास पहल

प्राधिकरण की टीम ने आईटी भूखंडों के आवंटन की शर्तों में सुधार पर कंपनियों के प्रतिनिधि से की बात

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने एक खास पहल की है। सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम आवंटियों और निवेशकों से मिलकर आईटी सेक्टर की अड़चनों और उनको हल करने के सुझाव प्राप्त कर रही है।

प्राधिकरण के वरिष्ठ अफसर भी इस काम में जुट गए हैं। दरअसल, ग्रेटर नोएडा में आईटी सेक्टर के लिए अपार संभावनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से भी ग्रेटर नोएडा एनसीआर के अन्य शहरों से आगे है। नोएडा एयरपोर्ट भी जल्द शुरू होने जा रहा है। यहां आईटी के लिए भूखंडों की पर्याप्त उपलब्धता है। प्राधिकरण जल्द ही स्कीम लाना चाह रहा है, लेकिन प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार की मंशा है कि मौजूदा आवंटियों और

एसीईओ सुनील कुमार सिंह और एसीईओ प्रेरणा सिंह ने पांच कंपनियों का किया भ्रमण

इच्छुक निवेशकों से मिलकर आईटी कंपनियों से जुड़ी समस्याओं और उनको हल करने के बाद आईटी भूखंड की स्कीम लांच की जाए।

सीईओ के निर्देश पर प्राधिकरण के आईटी विभाग की कंपनियों के प्रबंधन से संपर्क कर रही है। इस बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह और एसीईओ प्रेरणा सिंह ने भी हाल ही में टेकजोन-4 स्थित 5 कंपनियों, ओसियन इंफ्रा हाइट्स, एसपीआई आईटी, एडवांस कंप्यूसॉफ्ट, अर्था इंफ्राटेक और भूटानी आईटी पार्क का जायजा लिया। कंपनियों के प्रबंधन से आईटी सेक्टर की समस्याओं पर बात की।

वे लोग प्राधिकरण की आईटी भूखंडों के आवंटन की शर्तों में किस तरह का बदलाव चाहते हैं, भूखंड आवंटित होने के बाद उद्यम शुरू करने में क्या दिक्कत आ रही है, आईटी में किस कैटेगरी के वर्क का अधिक स्कोप है, इस तरह के तमाम मुद्दों पर दोनों अधिकारियों ने आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि से बात की और उनसे प्राप्त सुझावों को हायर अथॉरिटी के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण हर संभव कदम उठाने को तैयार है। आईटी कंपनियों से सुझावों को प्राप्त कर प्राधिकरण बोर्ड और षासन के समक्ष रखा जाएगा। प्राप्त अनुमति के आधार पर आगे कदम बढ़ाया जाएगा।

न्यू नोएडा बसाने के लिए जल्द होगा जमीनों का अधिग्रहण, किसानों से कराया जाएगा एग्रीमेंट

ग्रेटर नोएडा। न्यू नोएडा बसाने की दिशा में प्राधिकरण ने अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित योजना के तहत करीब 80 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे तथा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा देने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही किसानों और प्राधिकरण के बीच नए समझौता मॉडल पर भी विचार चल रहा है, जिससे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को विवाद रहित और आसान बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण के लिए एक नए विकल्प पर भी चर्चा चल रही है, जिसमें किसानों के साथ 11 महीने का एग्रीमेंट टू सेल किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत किसान पहले अपनी जमीन प्राधिकरण को बेचने के लिए सहमति देगा। यदि किसी कारणवश प्राधिकरण उस जमीन को नहीं लेता, तो किसान बाद में उसे किसी तीसरे पक्ष को बेच सकेगा। इस मॉडल का मकसद किसानों को भरोसा देना और अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि इससे किसानों और प्रशासन के बीच टकराव कम होगा और परियोजना समय पर आगे बढ़ सकेगी। न्यू नोएडा परियोजना को गति देने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी तैयार किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित तीन नायाब तहसीलदारों के नाम शासन स्तर से स्वीकृत हो चुके हैं और जल्द ही उनकी तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही न्यू नोएडा के लिए अस्थाई कार्यालय बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण और किसानों से संवाद की प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यालय स्थापित करना जरूरी है। संभव है कि जोखाबाद या सांवली गांव में अस्थाई कार्यालय बनाया जाए, ताकि ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित किया जा सके। न्यू नोएडा को लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाना है। इस विशाल परियोजना को चार चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 2023 से 2027 के बीच 3165 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित होगा, जबकि 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर जमीन विकसित की जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में 2032 से 2037 के बीच 5908 हेक्टेयर और अंतिम चरण में 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। प्राधिकरण पहले उन गांवों से अधिग्रहण शुरू कर सकता है जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और जीटी रोड के आसपास स्थित हैं।

ग्रेटर नोएडा को रेलवे का बड़ा केंद्र बनाया जाए : सुरेंद्र नागर

नोएडा। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने मंगलवार को सदन में ग्रेटर नोएडा को रेलवे का बड़ा हब बनाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने लंबी दूरी की ट्रेन के स्टॉपेज दादरी और बोड़ाकी स्टेशन पर करने के लिए कहा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद सुरेंद्र नागर ने कहा कि ग्रेटर

नोएडा की आबादी 12 लाख से अधिक है। यहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत आसपास के कई राज्यों के लोग रहते हैं। दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते हैं। इसके बावजूद लंबी दूरी की ट्रेन पकड़ने के लिए लोगों को ग्रेटर नोएडा से 50 किलोमीटर दूर गाजियाबाद या दिल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि ग्रेटर नोएडा के दादरी और बोड़ाकी रेलवे स्टेशन से रोजाना प्रयागराज रीवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस और शिवगंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन उनका ठहराव नहीं है। इन तीनों ट्रेनों के दादरी और बोड़ाकी में ठहराव की अनुमति दी जाए ताकि यहां के लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही जनहित में ग्रेटर नोएडा को रेलवे हब बनाने के लिए बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का जल्द विकास किया जाए।

सेक्टर-81 में वाहन से कुचलकर कंपनीकर्मी की मौत

नोएडा। सेक्टर-81 में अज्ञात वाहन ने कंपनीकर्मी को कुचल दिया। राहगीरों की मदद से घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झांसी निवासी नितिन कुमार ने फेज-2 थाने में शिकायत दी कि वह बरौला गांव में परिवार के साथ रहते हैं। उनके पिता महेश कुमार एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन के पास स्थित कंपनी में नौकरी करते थे। वह 27 जनवरी की रात करीब आठ बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आ रहे थे। सेक्टर-81 में अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया। इससे महेश के सिर, हाथ और सीने में गंभीर चोटें आईं। महेश काफी देर तक सड़क पर तड़पते रहे। राहगीर उन्हें अस्पताल लेकर गए। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। सेक्टर-58 निवासी आदित्य कुमार ने एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दी कि सेक्टर-130 में उनकी बहन रहती है। युवती 19 जनवरी को सुबह करीब 10 बजे सेक्टर-137 स्थित कंपनी में नौकरी करने जा रही थी। रास्ते में तेज रफ्तार कार चालक ने युवती को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बेहोश हो गई। लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब भी उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

एयरपोर्ट पर नौकरी के लिए युवा अखिलेश यादव से मिले

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थाई नौकरी की मांग को लेकर जेवर के युवा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर की। वादा के मुताबिक नौकरी न मिलने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात हुई।

युवाओं ने उन्हें बताया कि हैं। युवाओं का आरोप है कि नायल कभी 24 और कभी 33 युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रही, पर विस्थापित परिवार से आने वाले एक भी युवा को अब तक नौकरी नहीं मिली। जल्दी नौकरी न मिलने पर युवा एयरपोर्ट के गेट पर धरने पर बैठने का निर्णय लिया है।

अखिलेश यादव ने उनके समर्थन में आने का भरोसा दिया। इस मौके पर कई युवा मौजूद थे।

एयरपोर्ट में जमीन देने के लिए पांच लाख रुपये के बजाय उन्होंने रोजगार का विकल्प चुना। उन्हें भरोसा दिया गया कि उनका रोजगार स्थाई होगा, लेकिन अब तक किसी युवा को रोजगार नहीं मिला। एयरपोर्ट बना रही कंपनी किसी अन्य कंपनी के द्वारा भर्ती कर रही है, जिसका वह विरोध कर रहे

डीडीआरडब्ल्यूए ने नागरिक सुरक्षा को लेकर उठाए अहम मुद्दे

ग्रेटर नोएडा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रेजिडेंसी वेलफेयर संगठन गौतम बुद्ध नगर की ओर से मंगलवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। यह मांग पत्र संगठन के अध्यक्ष एनपी सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के एसीईओ सोमयेश श्रीवास्तव एवं एसीईओ लक्ष्मी वीएस को सौंपा गया।

संगठन की ओर से नोएडा सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत का उल्लेख करते हुए शासन, प्रशासन और प्राधिकरण से इससे सबक लेने

संगठन ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि प्रस्तावित सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए

की अपील की गई। मांग पत्र में कहा गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को निवासियों की जान-माल की सुरक्षा हेतु तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

मांग पत्र में प्रमुख रूप से क्विक रिस्पांस टीम के गठन की मांग की गई, ताकि किसी भी आपात स्थिति में एक जिम्मेदार एजेंसी तुरंत मौके पर पहुंच सके। इसके साथ ही रोड इंजीनियरिंग और यू-टर्न की व्यवस्था में सुधार, सड़कों को सही तरीके से जोड़ने, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर, साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता बताई गई। संगठन ने शहर में खुले पड़े बड़े नालों को कवर करने की मांग भी उठाई, ताकि किसी व्यक्ति या पशु के गिरने से जान-माल का नुकसान न हो। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में खुले नालों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

किराये पर ली थार से छात्र ने वाहनों को टक्कर मारी

ग्रेटर नोएडा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र ने किराये पर ली थार से सेक्टर अल्फा-1 में घर के बाहर खड़ी कार और बाइक को टक्कर मार दी। घटना का वीडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा थार को भी कब्जे में ले लिया।

सेक्टर बीटा-2 कोतवाली पुलिस के मुताबिक सेक्टर अल्फा-1 में घर के बाहर खड़ी एक कार और बाइक में थार से टक्कर मारने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मंगलवार की सुबह थार चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में पता है कि थार चालक युवराज नॉलेज पार्क के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर

रहा है। उसने सोमवार को लोनी के सिरोली गांव में अपने चचेरे भाई की शादी में जाने के लिए थार किराये पर ली थी। वह अपने दोस्तों के साथ थार लेकर बारात में जाने के लिए निकला था।

हड़बड़ाहट में उसकी थार सेक्टर अल्फा-1 में एक घर के बाहर खड़ी कार और बाइक से टकरा गई। थार की टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि थार को कब्जे में ले लिया गया है। चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

मीनू यादव उत्तर प्रदेश की सीनियर एकदिवसीय क्रिकेट टीम में चयनित

नोएडा। सेक्टर-122 स्थित पर्थला खंजरपुर निवासी उभरती क्रिकेटर मीनू यादव का उत्तर प्रदेश की सीनियर महिला एकदिवसीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनके चयन की खबर मिलते ही परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। मीनू यादव सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष सूबे यादव की पुत्री हैं और लंबे समय से अपने खेल के दम पर पहचान बना रही हैं। चयन प्रक्रिया के तहत लखनऊ में पहले दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इसके बाद चार दिवसीय कैंप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर एकदिवसीय टीम का चयन किया गया। मीनू यादव ने इस दौरान अपने शानदार खेल से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा।

वह तेज गेंदबाज होने के साथ-साथ बैटिंग में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश महिला एकदिवसीय टीम 6 फरवरी से गुजरात के राजकोट में शुरू होने वाली वनडे ट्रॉफी में हिस्सा लेगी। मीनू यादव के लिए यह मौका उनके कॅरिअर का अहम पड़ाव माना जा रहा है, जहां वह राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का

प्रदर्शन करेंगी। मीनू के चयन पर वरिष्ठ सपा नेता राघवेंद्र दुबे ने कहा कि मीनू यादव ने अपने परिश्रम, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर पूरे नोएडा का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और मीनू जैसी खिलाड़ी अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगी। स्थानीय खेल प्रेमियों और परिचितों ने भी मीनू यादव को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

संपादकीय

रक्षा बजट: इजाफे में छिपा निवेश

इतिहास के कुछ क्षण घटित फलत से नहीं बल्कि उसके बाद लिए गए निर्णायक फैसलों से परिणामोन्मुख होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रस्तुत 77.85 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट ऐसा ही एक निर्णायक क्षण है। यह बजट मात्र व्यय का विवरण नहीं, बल्कि भारत की बदली हुई सामरिक दृष्टि, अडिग आत्मविश्वास और भविष्य की सशक्त तैयारी का उद्घोष था। यह बजट महज व्यय का विवरण नहीं बल्कि देश की बदली हुई सामरिक शक्ति का उद्घोष है। रक्षा बजट में 15 फीसदी की यह वृद्धि इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी समझौते की नहीं, बल्कि सामर्थ्य, संकल्प और निर्णायक शक्ति के रूप में परिभाषित होगी। गत वर्ष के रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह वृद्धि असाधारण प्रतीत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में अनिवार्य है। विशेष रूप से पूंजीगत व्यय का 12.19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचना और उसमें 22 फीसदी का उछाल दर्शाता है कि भारत अब तात्कालिक जरूरतों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक शक्ति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि आधुनिक युद्ध तकनीक, तैयारी और आत्मनिर्भरता में भारत बजट आंकड़ों से आगे बढ़कर एक सशक्त रणनीतिक देश बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने जिस निर्णायक तरीके से दुश्मन के हवाई क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया, उसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की परंपरागत धारणाओं को बदल दिया। शत्रु ठिकानों का सटीक और प्रभावी विनाश के साथ संघर्ष विराम के लिए विवश करना केवल सैन्य सफलता नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक चेतावनी थी। यह बजट उसी चेतावनी को स्थायी सामरिक शक्ति में रूपांतरित करने का साधन बन रहा है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म, प्रत्येक प्रणाली और प्रत्येक हथियार को स्वदेशी बनाने की दिशा में यह एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम है। रक्षा मंत्री द्वारा इसे 'रणनीतिक अनिवार्यता' करार देना वर्तमान वैश्विक यथार्थ की सटीक और स्पष्ट व्याख्या है। मई 2025 के सीमित किंतु तीव्र संघर्ष ने यह उजागर कर दिया कि आतंक और अस्थिरता की जड़ें पड़ोसी भूभागों में गहराई तक फैली हुई हैं। ऐसे वातावरण में केवल रक्षात्मक रुख पर्याप्त नहीं, बल्कि आक्रामक, आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम सैन्य शक्ति की नितांत आवश्यकता है। इसी रणनीतिक सोच के अनुरूप इस बजट में विमानन, एयरो इंजन और अगली पीढ़ी की युद्ध प्रणालियों पर विशेष और स्पष्ट रूप से बल दिया गया है।

नर्सरी से कॉलेज तक, एडमिशन की युद्धभूमि

टीवी चैनलों पर दाख़िले को लेकर बहसें होती हैं, कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल-कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है—जिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है। कभी 60–65 प्रतिशत अंक लाना सम्मान की बात हुआ करती थी। सेकंड डिविज़न जीवन की हार नहीं मानी जाती थी। आज हालात यह हैं कि 90 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वाला बच्चा और उसके माता-पिता अपराधबोध में जीते हैं। 95–96 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी चैन नहीं है, क्योंकि कट-ऑफ़ हर साल नई ऊँचाई छू रहा है। ऐसा लगता है मानो अंकों की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ज़्यादातर बच्चे 90 प्रतिशत से ऊपर अंक ला रहे हैं, तो क्या वास्तव में सब असाधारण प्रतिभाशाली हैं? या फिर मूल्यांकन प्रणाली ही अपना संतुलन खो चुकी है? शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना था, लेकिन वह अब अंकों और रैंक के गणित में सिमट कर रह गया है। ज्ञान से ज़्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, और प्रदर्शन से ज़्यादा उसका प्रचार।

- डॉ० सत्यवान सौरभ

आज शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं, बल्कि साबित करना हो गया है। साबित करना कि बच्चा बेहतर है, तेज़ है, दूसरों से आगे है। और यह साबित करने की ज़िम्मेदारी बच्चे से ज़्यादा उसके माता-पिता के कंधों पर डाल दी गई है। नतीजा यह है कि नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, 'दाख़िला' अब एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव का कारण बन चुका है। दाख़िले की इस दौड़ में सबसे पहले निशाने पर आता है मासूम बच्चा। वह उम्र, जब खेलना, कल्पना करना और सवाल पूछना चाहिए, उसी उम्र में उसे फ़ॉर्म, इंटरव्यू, टेस्ट और रैंक के बोझ तले दबा दिया जाता है। नर्सरी एडमिशन के नाम पर माता-पिता छुट्टियाँ लेते हैं, स्कूल-दर-स्कूल भटकते हैं, सिफ़ारिशें ढूँढते हैं और कई बार आत्मसम्मान तक गिरवी रख देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि बच्चा सीख सके, बल्कि इसलिए कि वह 'अच्छे स्कूल' का टैग हासिल कर सके। आज शिक्षा संस्थान ज्ञान के मंदिर कम और प्रतिस्पर्धी बाज़ार ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अख़बारों में 'मिशन एडमिशन' जैसे शब्द आम हो चुके हैं।

टीवी चैनलों पर दाख़िले को लेकर बहसें होती हैं, कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल-कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है—जिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है। कभी 60–65 प्रतिशत अंक लाना सम्मान की बात हुआ करती थी। सेकंड डिविज़न जीवन की हार नहीं मानी जाती थी। आज हालात यह हैं कि 90 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वाला बच्चा और उसके माता-पिता अपराधबोध में जीते हैं। 95–96 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी चैन नहीं है, क्योंकि कट-ऑफ़ हर साल नई ऊँचाई छू रहा है। ऐसा लगता है मानो अंकों की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ज़्यादातर बच्चे 90 प्रतिशत से ऊपर अंक ला रहे हैं, तो क्या वास्तव में सब असाधारण प्रतिभाशाली हैं? या फिर मूल्यांकन प्रणाली ही अपना संतुलन खो चुकी है? शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना था, लेकिन वह अब अंकों और रैंक के गणित में सिमट कर रह गया है। ज्ञान से ज़्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, और प्रदर्शन से ज़्यादा उसका प्रचार। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भयावह पहलू है बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। परीक्षा, इंटरव्यू और चयन की अनिश्चितता बच्चे के भीतर डर और असुरक्षा पैदा करती है। असफलता की स्थिति में पहला सवाल यही होता है—"अब क्या होगा?" यह सवाल सिर्फ़ भविष्य का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी होता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी असफलता उसके माता-पिता की हार है। यह भाव उसके आत्मविश्वास को गहरे तक चोट पहुँचाता है। विडंबना यह है कि माता-पिता भी इस दबाव के शिकार हैं।

समाज ने उनके सामने सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा रख दी है—टॉप स्कूल, टॉप कॉलेज और टॉप करियर। वे यह सोचने से डरते हैं कि अगर उनका बच्चा इस तय ढाँचे में फिट नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। परिणामस्वरूप वे बच्चे की रुचि, क्षमता और स्वभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता इस समस्या को और गंभीर बना देती है। जिनके पास संसाधन हैं, वे महँगी कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और मैनेजमेंट कोटा खरीद सकते हैं। लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह दौड़ कहीं ज़्यादा कठिन है। योग्यता के बावजूद अवसर न मिलना, व्यवस्था पर से भरोसा तोड़ देता है। धीरे-धीरे शिक्षा सामाजिक न्याय का माध्यम न रहकर विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाती है। एक और चिंताजनक पहलू यह है कि हम बच्चों को सोचने के बजाय रटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले बच्चे 'डिस्ट्रैक्टेड' माने जाते हैं और उत्तर याद करने वाले 'मेधावी'। रचनात्मकता, संवेदनशीलता और नैतिकता जैसे गुण पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं।

शिक्षा का लक्ष्य इंसान बनाना था, लेकिन हम मशीन तैयार करने में लगे हैं। इस संदर्भ में यह सवाल बेहद ज़रूरी है—क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ टॉपर पैदा करना है? या ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज के प्रति ज़िम्मेदार हों, सवाल पूछ सकें और बदलाव ला सकें? जब तक हम इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर नहीं खोजेंगे, तब तक दाख़िले की यह दौड़ और ज़्यादा बेरहम होती जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को बाज़ार से मुक्त किया जाए और मूल्यांकन प्रणाली को मानवीय बनाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और अवसरों को समान बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हों। सबसे ज़रूरी है माता-पिता और समाज की सोच में बदलाव—कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता। अगर शिक्षा को आनंद, जिज्ञासा और आत्मविकास का माध्यम बना दिया जाए, तो दाख़िले की यह दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी। वरना हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भविष्य सौंपेंगे, जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, लेकिन संतुलन और संवेदनशीलता नहीं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रुककर सोचें—क्या शिक्षा का मक़सद केवल टॉपर पैदा करना है, या संवेदनशील, सोचने-समझने वाला इंसान बनाना? जब तक दाख़िले की यह अंधी दौड़ जारी रहेगी, तब तक शिक्षा बोझ बनी रहेगी, आनंद नहीं। बदलाव सिस्टम में चाहिए, लेकिन शुरुआत हमारी सोच से होगी—वरना यह दौड़ हर साल और बेरहम होती जाएगी।

कर्तव्य बजट : रोजगार, संसाधन और विकास

-हेमेन्द्र क्षीरसागर-

देश की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2026 के प्रस्तुत केन्द्रीय आम बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसकी पड़ताल करे तो हम पाएंगे पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा केंद्रित निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर विकास और कम मुद्रास्फीति के साथ लगातार बढ़ी है। प्रस्तावित बजट में रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता और घरेलू क्रय शक्ति के लिए सुधार लागू किए गए। 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 350 से अधिक सुधारों को लागू किया गया है। इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है।

रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति मिल रही है। सीमा शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष करों के साथ-साथ प्रत्यक्ष कराधान उपायों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और बोझिल नियमों को कम करके क्रमशः हमारे नागरिकों और व्यवसायों के लिए जीवन सुगमता और व्यापार सुगमता में सुधार करना है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 में प्रधानमंत्री के साथ कई नवीन विचारों को साझा किया गया। जिन्होंने कई प्रस्तावों को प्रेरित किया है, जिससे यह

एक अद्वितीय युवा शक्ति-संचालित बजट बन गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प गरीबों, वंचितों और वंचितों का समर्थन करना है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर और अस्थिर वैश्विक गतिशीलता के लिए लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना। अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और क्षेत्र की सार्थक भागीदारी के लिए संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच हो। सबका साथ, सबका विकास और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना।

आर्थिक विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए, बजट 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है। रणनीतिक और सीमांत क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ाना। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए बजट में बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल उन्नति के लिए रणनीति) की शुरुआत की गई है। जो घरेलू जीवविज्ञान और बायोसिमिलर उत्पादन के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की पहल है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन, भारतीय आईपी के पूर्ण स्टैक को डिजाइन करने और सेमीकंडक्टर्स की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करना। औद्योगिक क्षेत्रों की विरासत का कायाकल्प। बुनियादी ढांचे को एक शक्तिशाली बढ़ावा देना। वित्त वर्ष 2026-27 में बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो अब तक का सबसे अधिक है। राज्यों को विशेष सहायता आवंटित करके सुधारों को लागू करने और उत्पादक खर्च में शामिल होने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में हर जिले में महिला छात्रावास की स्थापना। पांच आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के तहत मेडिकल हब बनाना। आयुष मिशन को विशेष प्रोत्साहन। कैंसर के मरीजों को बजट में बड़ी राहत मिली। महंगी दवाइयों से हटा कर, अब सस्ता होगा इलाज। रेलवे के क्षेत्र में 2.78 लाख करोड़ का बजट। 7 बूलेट ट्रेन रेलवे कोरिडोर। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन एवं तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता मिशन। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए का प्रावधान। गांवों को विकास का इंजन बनाने के लिए आवंटन। दिव्यांग जन कौशल विकास और प्रशिक्षण योजना लागू करना इत्यादि शामिल हैं। जैसे विकल्प देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प अवश्य पूरा करेंगे। जिसकी उम्मीद देशवासियों ने देश की सरकार से लगाईं थी, जो प्रस्तुत बजट में दिखाई पड़ी।

जन्म-मरण के चक्र से मुक्त कराती है गीता

अनन्त शास्त्र है, विद्याएं भी बहुत हैं और हमारी आयु इतनी स्वल्प है कि रोग-शोकादि, विघ्न-बाधाओं से भरी इस छोटी अवधि में उनका पार पाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है, अतः बुध्दिमता इसी में है कि इन शास्त्रों की सारभूत बातों को ग्राहण करके आत्मोध्दार कर लिया जाए।

वेदोपनिषदों का सारः- शास्त्रों की इसी अनन्ता और मानव-जीवन की क्षणभंगुरता को ध्यान में रखकर धर्म संस्थापनार्थ अवतार ग्रहण करने वाले साक्षात ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण ने मानवों के कल्याण के लिये उन समस्त ज्ञान-विज्ञान विषयक विधिक शास्त्रों के साररूप गीता-ग्रंथ को हमारे लिये उपलब्ध करवा दिया। श्रीमद्भगवद् गीता समस्त वेदोपनिषदों का सार-रूप है। इसकी अनन्त महिमा है। यह वह ब्रह्मविद्या है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य जन्म-मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है। यह भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग से समन्वित एक समग्र योगशास्त्र है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यन्त प्रगाढ़ और प्रभावपूर्ण ढंग से योग के विविध रूपों के द्वारा प्राप्त होने वाली मानव-पुरुषार्थ की विभिन्न उपलब्धियों का, जीवन के लक्ष्य का, धर्म के निगूढ़ तत्वों का, भक्ति-ज्ञान और कर्म के मार्ग का बड़ी ही सरल शब्दावली में रहस्योद्घाटन किया है। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं इस गीताशास्त्र की प्रशंसा में कहा है कि

अध्येच्यते चय इमं धम्र्य संवादभावयोः।
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः।
श्रध्दाज्ञवाननसूयश्च शणुयादापि यो नरः।
सो पिमुक्तः शुमांल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्॥

अर्थात् जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों (श्रीकृष्ण और अर्जुन) के संवादरूप इस गीताशास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मनुष्य श्रध्दायुक्त और दोषदृष्टि से रहित होकर इस गीताशास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के समान श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जायेगा। हमारा मन आंतरिक संग्राम के लिये महाभारत का कुरुक्षेत्र है जहां हर क्षण संग्राम जारी रहता है, अतः हम सबको ज्योति, ज्ञान तथा सन्मति प्राप्त करनी चाहिये जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया है।

आज का इतिहास

1620 - हंगरी के प्रिंस बेथलेन और रोम के सम्राट फर्डीनेंड द्वितीय के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।
1628 - शाहजहाँ को आगरा में मुग़ल बादशाह का ताज पहनाया गया।
1783 - इटली के कैलब्रिया में आये भीषण भूकंप में 50 हजार लोग मारे गये।
1797 - इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो में आये विनाशकारी भूकंप में 41 हजार से अधिक लोग मारे गये।
1847 - मैरीलैंड में अमेरिका की पहली टेलीग्राफ कंपनी की स्थापना की गयी।
1881 - लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र 'केसरी' का पहला अंक आया था।
1895 - अमेरिका के शिकागो में पहले रोलिंग लिफ्ट पुल का उद्घाटन हुआ।
1920 - लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली विमान सेवा शुरू।
1924- महात्मा गांधी को उनका ख़राब स्वास्थ्य होने के कारण समय से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया।
1932 - न्यूयार्क के लेक प्लेसिड में तीसरे शीतकालीन ओलंपिक का शुभारंभ।
1948 - सिलोन (अब श्रीलंका) को ब्रिटेन से आजादी मिली।
1960 - भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ।
1965 - अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
1968 - केन्या से एशियाई नागरिकों के पलायन का सिलसिला जारी। भारत और पाकिस्तान के 96 लोग ब्रिटेन पहुंचे, जिनमें नौ छोटे बच्चे शामिल थे।
1973 - भारत के सबसे बड़े मर्चेंट पोत जवाहरलाल नेहरू का उद्घाटन। इसमें 88,000 डीडब्ल्यूटी का सुपर टैंकर था।
1976 - ग्वाटेमाला में भीषण भूकंप में 23,000 लोगों की मौत हो गई और 75,000 से ज्यादा जख्मी हुए।
1976 - संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने कहा कि वह निरक्षरता को दूर करने के अपने प्रयासों में असफल रहा है। इस संबंध में संगठन का दस वर्ष का कार्यक्रम भारत सहित 11 देशों पर केंद्रित था।

विकासशील देशों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करना होगा

-डॉ. अरुण मित्रा-

'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मगा) के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नज़रअंदाज़ करते हुए एकतरफ़ा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, 'अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है।' वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) की 56वीं सालाना बैठक, जो 19-23 जनवरी 2026 को दावोस में 'ए स्पिरिट ऑफ़ डायलॉग' थीम के तहत हुई, वह वैश्विक व्यापार संबंधों में भारी तनाव के माहौल में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों ने देशों के बीच सहयोग के बने-बनाए ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यह आम तौर पर महसूस किया गया कि वैश्विक लड़ाई से बचने के लिए अलग-अलग देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना ज़रूरी है। इसी संदर्भ में, बातचीत और अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साझे मंच के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों- संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ (अब रूस), फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन- को दी गई ज़्यादा शक्ति के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने शांति और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, नाभिकीय हथियारों के खतरों को जोरदार ढंग से सामने लाने, बच्चों की भलाई,सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाने और इंसानों की बनाई और कुदरती, दोनों तरह की मुश्किलों से निपटने में अहम भूमिका निभायी है। इसने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने में भी मदद की है।

1964 में बनी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) का मकसद विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास से फायदा पहुंचाने में मदद करना और उन्हें बराबरी की शर्तों पर विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना था। अंकटाड नीति विश्लेषण देकर, आम सहमति बनाने में मदद करके और खासकर कम विकसित देशों (एलडीसी) को तकनीकी मदद देकर व्यापार और विकास के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के तौर पर काम करता है। इसी तरह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट), जो 1947 की एक बहुपक्षीय संधि थी, ने टैरिफ, कोटा और सब्सिडी में कमी करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाकर युद्ध के बाद आर्थिक सेहत में सुधार को तेज़ करने की कोशिश की। 1995 में, गैटकी जगह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने ले ली। हालांकि डब्ल्यूटीओ की विकसित देशों के पक्ष में होने के लिए बहुत आलोचना हुई है, लेकिन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) और ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेज़र्स (ट्रिम्स) जैसे समझौतों के कई प्रावधानों का इस्तेमाल विकासशील देश अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि इन व्यवस्थाओं ने कम से कम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नियम-आधारित प्रणाली दी। 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (मगा) के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नज़रअंदाज़ करते हुए एकतरफ़ा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, 'अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है।' उन्होंने मध्यम आय वाले देशों से एकजुट होने की अपील की। यह ट्रंप की नीति की अप्रत्यक्ष आलोचना थी और उसका विरोध था। ट्रंप ने अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग बातचीत करके अपना टैरिफ एजेंडा लागू करने की कोशिश की, जिससे बहुपक्षवाद कमज़ोर हुआ। उनके इरादे तब और साफ़ हो गए जब उन्होंने पनामा कैनाल और गल्फ ऑफ़ मेक्सिको पर नियंत्रण और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैश्विक तेल संसाधनों में अपनी दिलचस्पी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वेनेजुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण ने दुनिया भर में राष्ट्रीय सम्प्रभुता के लिए सीधी चुनौती पेश की। इस प्रक्रिया में, ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक साथियों को भी कमज़ोर किया। कई यूरोपीय देशों ने पहले इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य दखल का समर्थन किया था, सीरिया में बागी ताकतों का साथ दिया था, और ईरान में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने की कोशिशों का समर्थन किया था। गाजा में नरसंहार के दौरान भी, उन्होंने हल्के-फुल्के एतराज़ के साथ इज़राइल का साथ दिया था। पहले, वे पुराने सोवियत संघ से पैदा किए गए खतरे के जवाब में अमेरिका के साथ थे। लेकिन, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ज़बरदस्ती या खरीदकर कब्ज़ा करने का प्लान बताया, तो इन देशों को अमेरिका के एकतरफ़ा फ़ैसले का असर महसूस होने लगा। नतीजतन, यूरोपियन यूनियन के देश, जिनमें से कुछ कभी औपनिवेशिक ताकतें थीं, अमेरिकी चुनौती का सामना करने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगे। यह घटनाक्रम वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को मज़बूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसी संदर्भ में, लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौता- जिस पर 2007 से बातचीत चल रही थी- 27 जनवरी 2026 को पूरा हुआ। इस समझौते पर सावधानी से नज़र रखनी होगी क्योंकि ईयू की बड़ी मांगें- जिसमें बौद्धिक सम्पदा, सरकारी खरीद, खेती और नियामक मानक भी शामिल हैं- भारत के विकास, औद्योगिक विकास, और जन कल्याण के लिए नीतिगत जगह को हमेशा के लिए रोकना चाहती हैं, जो भारत की आर्थिक सम्प्रभुता, रणनीतिगत स्वायत्तता और नागरिकों की भलाई का एक गलत उल्लंघन है। साथ ही, टैरिफ खत्म होने से बाजार में बाढ़ आ जाएगी। इससे विनिर्मित सामान की भी बाढ़ आ जाएगी, जिससे भारत में उद्योगीकरण में विलोम गति (डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन), बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान और सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) का विनाश होगा। इसके अलावा, ईयू की प्रस्तावित बौद्धिक सम्पदा प्रणाली भारत के जेनेरिक दवाओं के सेक्टर को पंगु बना देगा, जिससे ज़रूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ धोखा होगा। भूमंडलीय वैश्विक राजनीति में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, और नए रुझान सामने आ रहे हैं। इस नाजुक मोड़ पर, वैश्विक दक्षिण के विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता के सम्मान, हथियारों की होड़ को खत्म करने और आपसी फायदे पर आधारित आर्थिक विकास की अपनी प्रणाली विकसित करना ज़रूरी है। हाल के सालों में, कई विकासशील देश मदद के लिए तेज़ी से चीन की ओर मुड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) में इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहल एक सकारात्मक कदम है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एससीओ) जैसे प्लेटफॉर्म का उभरना भी उत्साहजनक है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक आदित्य वशिष्ठ द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी-42 सेक्टर-7 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से मुद्रित व ए-152, सैक्टर 63, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301 से प्रकाशित।
संपादक - आदित्य वशिष्ठ   कानूनी सलाहकार-पवित्र मोहन शर्मा   आर.एन.आई.- UPHIN/2023/84499
इस अंक में प्रकाशित सभी समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी होंगे।   e-mail: Jbttimes2021@ gmail. Com

केंद्रीय बजट देश में घटती बेरोजगारी और केंद्र-राज्य की साझा विकास दृष्टि है : मोहन यादव

मोदी सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और उद्यमिता विकास पर फोकस

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश में घटती बेरोजगारी और केंद्र-राज्य की साझा विकास दृष्टि है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर घटकर मात्र 1.5 प्रतिशत रह गई है। यह आंकड़ा प्रदेश की आर्थिक सेहत को दर्शाता है।

प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को केंद्रीय बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह भी संकेत देता है कि राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में तेजी से सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित नीतियों, निवेश-अनुकूल वातावरण और उद्योगों के विस्तार का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट 'एक आत्मा, एक लक्ष्य' के सिद्धांत पर आधारित है। ये बजट राज्य और केंद्र के पूरक है और देश व प्रदेश को दीर्घकालिक विकास की दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार, केंद्रीय बजट कागजी दस्तावेज न होकर भविष्य का ठोस रोडमैप है, जोकि निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सक्षम है।

मुख्यमंत्री ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट के पहले और बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वे इसके प्रभाव को दर्शाती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसे अमेरिका जैसे देशों से कर्ज लेने के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता है, जबकि भारत आज अपनी नीतियों और संसाधनों के बल पर आगे बढ़ रहा है। यह अंतर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और वैश्विक विश्वास का प्रमाण है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 5000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इससे शहरी बुनियादी ढांचे, परिवहन, आवास और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी।

इसके साथ ही छोटे शहरों और तीर्थ स्थलों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बजट में अहम प्रावधान किए गए हैं। हर जिले में एक महिला छात्रावास के निर्माण से छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास मिलेगा। जिला अस्पतालों के उन्नयन से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल स्थलों के विकास से मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में केयर इकोसिस्टम पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे बुजुर्गों के इलाज और देखभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी। गंभीर बीमारियों की दवाइयों के सस्ते होने से आम नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सुधारों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की सौगात दी गई है। इस परियोजना से लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार और 6 लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। यह पार्क विशेष रूप से मालवा-निमाड़ अंचल के लिए आर्थिक उछाल का माध्यम बनेगा और क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगा। बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया गया है। इससे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए उच्च कौशल वाले रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को बजट का बड़ा लाभार्थी बताते हुए कहा कि औद्योगिक विकास से प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, केंद्रीय बजट और आगामी मध्य प्रदेश बजट राज्य को आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और सामाजिक संतुलन की दिशा में आगे ले जाने वाले सिद्ध होंगे। घटती बेरोजगारी, बढ़ता निवेश और केंद्र-राज्य का मजबूत समन्वय यह स्पष्ट संकेत देता है कि मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि ध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2026-27 का बहुप्रतीक्षित बजट आगामी 18 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

बजट से पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति, रोजगार के अवसरों और विकास की दिशा को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि यह केंद्रीय बजट आने वाले 10 वर्षों में भारत की विकास दिशा तय करेगा। रणनीतिक उत्पादों के निर्माण, अलग मालगाड़ी कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी जैसे प्रावधान व्यापार को नई गति देंगे। उन्होंने इसे डर से मुक्त टैक्स व्यवस्था की ओर बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे भारत की आर्थिक संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने वाला बताया।

अमेरिका-भारत व्यापार समझौता मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा: शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएगा और इससे व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे तथा परस्पर विकास को बढ़ावा मिलेगा।

शाह ने सोमवार देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों और उनके नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा तथा इससे भारत एवं अमेरिका के बीच व्यापार के और फलने-फूलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत-अमेरिका संबंधों के लिए यह एक बड़ा दिन है, क्योंकि 18 प्रतिशत की काफी कम की गई शुल्क (टैरिफ) दर के साथ व्यापार समझौता तय हुआ है, जो मजबूत व्यापारिक रिश्तों और आपसी विकास का रास्ता खोलेगा। इस 'ऐतिहासिक समझौते' के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए शाह ने कहा कि यह सौदा 'हमारी रणनीतिक साझेदारी को और ऊंचाइयों पर ले जाएगा तथा दोनों देशों एवं उनके लोगों को भारी लाभ पहुंचाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और अधिक फलेगा-फूलेगा।' भारत और अमेरिका के बीच हुए इस व्यापार समझौते के तहत वाशिंगटन भारतीय वस्तुओं पर लगाए जाने वाले पारस्परिक शुल्क को मौजूदा 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि अब 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर कम शुल्क लगेगा।

जेल में नशीला पदार्थ पहुंचाने की बड़ी साजिश नाकाम

फरीदाबाद। जिला कारागार फरीदाबाद में जेल प्रशासन की सतर्कता, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तथा त्वरित कार्रवाई के चलते नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक गंभीर साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया। सूचना के आधार पर उप- अधीक्षक (सुरक्षा) की निगरानी में गठित जेल स्टाफ की विशेष टीम द्वारा सोमवार को सघन तलाशी अभियान चलाया गया।

इस दौरान बैरक नंबर-18 के समीप तीसरे कोर्ट की दीवार के पास टेप में लिपटी एक बॉल बरामद की गई, जो पीले, सफेद एवं गुलाबी रंग की थी तथा जिस पर राजा गोल्ड अंकित था। जांच करने पर बॉल के भीतर सुल्फानुमा नशीला पदार्थ पाया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त नशीली वस्तु को विचाराधीन बंदी बल्लभगढ़ निवासी मोहित पुत्र दिनेश, के निर्देश पर जेल परिसर में फिंकवाया गया था। इस साजिश को अंजाम देने हेतु पवन पुत्र कुमेरपाल, जो हाल ही में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था, द्वारा जेल के बाहर से बॉल फेंकी गई। इसके अतिरिक्त, जेल के भीतर से निगरानी कैदी गौरव पुत्र धर्मबीर की संलिप्तता भी सामने आई है।

बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन 17 ग्राम पाया गया है। इस प्रकरण में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु थाना सदर बल्लभगढ़ को सूचना प्रेषित कर दी गई है।

जेल प्रशासन फरीदाबाद द्वारा समय रहते की गई इस प्रभावी कार्रवाई से जेल परिसर में नशीले पदार्थों की आपूर्ति के प्रयास को सफलतापूर्वक रोका गया है। प्रशासन भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी निगरानी एवं सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया सात माह बाद नाभा जेल से रिहा

चंडीगढ़। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला की जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को करीब सात माह बाद नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद मजीठिया के वकील आज जेल पहुंचे और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी मजीठिया को जेल में बंद करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है। पंजाब से लेकर गुजरात तक पार्टी मंचों से कहती रही कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे, उन्हें हमने जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को नाभा जेल से बाहर आते ही मजीठिया ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मूंछों को ताव दिया। उनके साथ उनकी पत्नी गनीव कौर भी मौजूद थी। मजीठिया ने कहा कि धन-धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का। गुरु साहिब की अपार कृपा। जितना सरकार ने दबाया, उतनी ताकत मिली। दिल्ली हुक्मरानों के साथ ईंट से ईंट टकरानी है। मुझे इस बात की प्रेरणा मिली है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पिछले साल 25 जून को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक वह जेल में ही थे।

'परीक्षा पे चर्चा' का नौवां संस्करण 6 फरवरी को प्रधानमंत्री ने एपिसोड देखने का किया आह्वान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से 6 फरवरी को प्रसारित होने वाले 'परीक्षा पे चर्चा' (पीपीसी) के विशेष एपिसोड को देखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और सामूहिक भावना को दर्शाने वाला एक प्रेरणादायक मंच है।

'परीक्षा पे चर्चा' का नौवां संस्करण 6 फरवरी को सुबह 10 बजे आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से संवाद करेंगे। इस वर्ष कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न हिस्सों के विद्यार्थियों के साथ बातचीत की गई है। देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी के छात्र पहले ही संवाद में शामिल हो चुके हैं, जबकि नई दिल्ली स्थित 7, लोक कल्याण मार्ग पर भी छात्रों से विशेष चर्चा की गई। परीक्षा के मौसम से पहले आयोजित इस संवाद में प्रधानमंत्री ने एग्जाम वॉरियर्स के साथ बातचीत करते हुए तनावमुक्त परीक्षा, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास और संतुलन बनाए रखने जैसे विषयों पर व्यावहारिक सुझाव साझा किए। उन्होंने छात्रों के उत्साह और खुलेपन की सराहना करते हुए इन अनुभवों को ताजगी भरा और प्रेरक बताया। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, वैसे-वैसे 'परीक्षा पे चर्चा' भी लौट आई है और सभी को यह विशेष एपिसोड अवश्य देखना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री छात्रों से जुड़कर परीक्षा से जुड़े तनाव, तैयारी और अन्य चिंताओं पर चर्चा करते हैं। इस वर्ष पहली बार अलग-अलग क्षेत्रों के छात्रों को एक साथ जोड़ा गया है। इससे पहले यह कार्यक्रम केवल नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होता था। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो और निजी चैनलों पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय, दूरदर्शन, मायगव, यूट्यूब, फेसबुक लाइव और स्वयंप्रभा चैनलों पर भी इसे देखा जा सकेगा।

साल 2018 में शुरू हुए 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में अब तक करोड़ों छात्र, शिक्षक और अभिभावक भाग ले चुके हैं। पीपीसी 2026 के लिए अब तक 4.19 करोड़ से अधिक छात्रों, 24.84 लाख शिक्षकों और 6.15 लाख अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। यह कार्यक्रम सरकार के 'एग्जाम वॉरियर्स' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा के दबाव को कम करना है।

बीस फीट गहरे गड्ढे की मिट्टी ढहने से दो युवकों की मौत

पाली। जिले के चंडावल थाना क्षेत्र में मंगलवार को चंडावल से केरिया बेरा मार्ग पर बावरियों की ढाणी में 20 फीट गहरे गड्ढे की मिट्टी अचानक ढहने से चार युवक उसमें दब गए। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

सोजत सिटी सीओ रतनाराम देवासी ने बताया कि हादसे में महेंद्र कुमार (34) पुत्र सम्पतराम बावरी और लक्ष्मण (26) पुत्र बालूराम बावरी की मौत हो गई। दोनों के शव सोजत सिटी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। वहीं जवरीलाल (26) पुत्र सम्पतलाल बावरी और मनोहर (42) पुत्र सम्पतलाल बावरी घायल हो गए,

जिनका सोजत अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार बावरियों की ढाणी में ट्यूबवेल से करीब 300 फीट दूर स्थित एक खुले कुएं का जलस्तर बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल से कुएं तक कनेक्शन किया जा रहा था। इसके लिए करीब 40 फीट लंबा और 20 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था।

लोकसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

नई दिल्ली। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने पर हुए हंगामे के चलते कांग्रेस के 7 सहित कुल 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र से निलंबित किए जाने के खिलाफ पार्टी सांसदों ने संसद भवन के बाहर मकर द्वार पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। कांग्रेस ने अपने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली

बार नेता प्रतिपक्ष को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने से रोका गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भारी दबाव है और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर उन्हीं कारणों से किए गए हैं। हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। इन सांसदों में कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, मणिक्कम टैगोर, हिबी ईडन, प्रशांत पडोले, किरण रेड्डी और जिन कुरियोकोज के साथ तमिलनाडु से सीपीएम सांसद के एस वेंकटेश्वरन शामिल हैं।

स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मध्यप्रदेश से आएंगी ईवीएम

जयपुर। राजस्थान में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारु, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच मंगलवार को एक अतिरिक्त समझौता ज्ञापन (एडिशनल एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट और 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराएगा। इन ईवीएम का उपयोग नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि यह एमओयू दोनों राज्यों के बीच पहले से हुए ईवीएम समझौते का विस्तार है। उन्होंने कहा कि ईवीएम की आपूर्ति से लेकर उपयोग, रख-रखाव, सुरक्षा और वापसी तक की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी। उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि यह आपसी समन्वय न सिर्फ संघीय ढांचे को मजबूत करता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी अधिक भरोसेमंद बनाता है।

चुनावों के दौरान ईवीएम की सुरक्षा, परिवहन, भंडारण और संचालन तय प्रोटोकॉल के तहत होगा। ईवीएम का तकनीकी परीक्षण (एफएलसी), मरम्मत और तकनीकी सहयोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। समझौते में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ईवीएम के परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी स्टाफ की यात्रा से जुड़े खर्च नियमानुसार वहन किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम की वापसी, परीक्षण और किसी भी प्रकार की क्षति की स्थिति में प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार श्रीवास्तव, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश वर्मा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस समझौते के साथ ही राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां अधिक तेज हो गई हैं।

एसआईआर 'पीड़ितों' को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जा रहा : ममता

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से प्रभावित लोगों को अपना बचाव करने का अवसर नहीं दिया जा रहा और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया। बंगाल में एसआईआर 'पीड़ितों' के साथ यहां संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वे उन कई अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें इस प्रक्रिया के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

बनर्जी ने दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे पीछे बैठे सभी लोग एसआईआर के पीड़ित हैं। मैं यहां लाखों लोगों को ला सकती थी। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने आरोप लगाया, ₹वे एसआईआर पीड़ितों को अपना बचाव

करने का मौका नहीं दे रहे हैं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और अन्य नेता इनमें से कुछ लोगों को लेकर एसआईआर मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, लेकिन बनर्जी बाद में विरोध जताते हुए बैठक से बीच में ही बाहर निकल गईं और दावा किया कि उनके प्रतिनिधिमंडल का अपमान हुआ है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। एसआईआर के समय पर सवाल उठाते हुए बनर्जी ने मंगलवार को सवाल किया कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह प्रक्रिया क्यों की जा रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह प्रक्रिया केवल विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ही क्यों की जा रही है, भाजपा शासित असम में क्यों नहीं, जहां चुनाव होने हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव वाले चार राज्यों में से तीन राज्यों में वे एसआईआर कर रहे हैं, लेकिन भाजपा शासित असम में नहीं। बनर्जी ने पूछा कि चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों किया जा रहा है? क्या बिना किसी योजना के इसे 2-3 महीनों के भीतर करना संभव है? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले चाणक्यपुरी के 'बंग भवन' में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और दावा किया कि वे पात्र मतदाता हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए।

तेज रफ्तार दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, तीन घायल

बक्सर। चौसा-कोचस मुख्य मार्ग पर राजपुर थाना क्षेत्र के मकोरियाडीह गांव के समीप मंगलवार को तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन घायलों का इलाज जारी है। मृतक की पहचान धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव निवासी 30 वर्षीय प्रवीण पांडेय, पिता चंद्रभूषण पांडेय, के रूप में हुई है। घायलों में मानिकपुर गांव निवासी 26 वर्षीय नीरज पांडेय (पिता स्व. झरोरा पांडेय), 45 वर्षीय विनीत उर्फ छोटू पांडेय (पिता हृदयशंकर पांडेय) और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय गोलू कुमार (पिता भोला साह) शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रवीण पांडेय अपने दोस्तों के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर बक्सर की ओर जा रहे थे। मकोरियाडीह के पास बगल से गुजर रही पिकअप से बचने के प्रयास में उन्होंने ओवरटेक किया, तभी विपरीत दिशा से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए और सभी सवार सड़क पर गिर पड़े।

सीएम योगी ने वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम 'उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0' का किया शुभारंभ

कानून के राज में ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी बनी यूपी की पहचान: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को होटल ताज में आयोजित वैश्विक निवेशकों एवं उद्यमियों के महासंगम "उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0" का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज केवल एक राज्य नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भरोसे की गारंटी बन चुका है। प्रदेश सरकार हर निवेशक को ट्रिपल-एस यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की पूर्ण गारंटी देती है और उत्तर प्रदेश आज ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी का रोल मॉडल बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ पूरी मजबूती से लागू है। कानून से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। यदि कोई कानून को आंख दिखाने की कोशिश करता है, तो कानून अपने दायरे में लाकर उसे उसकी ही भाषा में जवाब देता है। यह नया उत्तर प्रदेश है, जहां व्यवस्था कमजोर नहीं, बल्कि निर्णायक है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश असुरक्षा, अराजकता और अविश्वास का पर्याय बन चुका था। वर्ष 2012 से 2017 के बीच प्रदेश में 900 से अधिक दंगे हुए। शायद ही कोई शहर रहा हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। उद्योग, व्यापार और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को गुंडा टैक्स देना पड़ता था। सुरक्षा के अभाव में पहले से स्थापित उद्योग भी प्रदेश छोड़ने पर मजबूर थे, युवा वर्ग पलायन कर रहा था। जिस धरती पर बचपन बीता हो, उसे छोड़ना किसी के लिए भी पीड़ादायक होता है, लेकिन असुरक्षा के चलते मजबूरी थी। यह केवल किसी एक उद्यमी की पीड़ा नहीं थी, बल्कि हर व्यापारी, हर निवेशक और हर नागरिक की व्यथा थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यह दायित्व सौंपा, तो सबसे बड़ी चुनौती कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करना था। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। हमने स्पष्ट कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। आज इसका परिणाम सबके सामने है। बड़े पर्व-त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहे हैं। कहीं दंगे नहीं, कहीं फिरौती नहीं, कहीं गुंडा टैक्स नहीं। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का वातावरण है और यही निवेश की सबसे मजबूत नींव है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज डी-रेगुलेशन रैंकिंग में देश में नंबर वन है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप अचीवर बन चुका है। डी-क्रिमिनलाइजेशन के तहत 13 राज्य अधिनियमों में मौजूद आपराधिक प्रावधानों को समाप्त किया गया, ताकि उद्योग बिना भय और बाधा के कार्य कर सकें। एमएसएमई सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को 1000 दिनों तक निरीक्षण से छूट दी गई है। कई अन्य सेक्टरों में भी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। सरकार का उद्देश्य उद्योगों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें सुविधा देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में लगभग 14,000 कारखाने कार्यरत थे, जो आज बढ़कर 30,000 से अधिक हो चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि डबल इंजन सरकार डबल स्पीड से काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 20 लाख करोड़ प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है और कई प्रोजेक्ट्स में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। निवेशकों के साथ सरकार का निरंतर संवाद बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए ठोस नीति और स्पष्ट विजन के साथ कार्य किया जा रहा है। ललितपुर में विकसित किया जा रहा बल्क ड्रग फार्मा पार्क केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं होगा, बल्कि इसे हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक आर एंड डी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क, यूएस-एफडीए टेस्टिंग लैब और वर्ल्ड-क्लास लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जा रहे हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र के माध्यम से लखनऊ में एक वर्ल्ड-क्लास फार्मा इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया जाएगा।

बरेली सहित अन्य जनपदों में भी नए फार्मा पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 'लोकल को ग्लोबल' बनाने का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश का लगभग 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में 60 प्रतिशत उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछले नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश के लगभग 55 प्रतिशत एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हैं। हर जिला मुख्यालय फोरलेन से जुड़ा है। बेहतर रेल नेटवर्क, सर्वाधिक मेट्रो सेवाएं, देश का पहला इनलैंड वाटरवे और सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिनमें चार अंतरराष्ट्रीय हैं और पांचवें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जल्द ही प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। यहां जीरो पॉलिटिकल इंटरफेयर, पारदर्शी नीतियां और समयबद्ध इंसेंटिव वितरण सुनिश्चित किया गया है। आइए निवेश करें, उत्पादन करें और समय पर इंसेंटिव प्राप्त करें, यही उत्तर प्रदेश का मॉडल है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू नहीं, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मा कॉन्क्लेव उसी संकल्प का हिस्सा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। एआई, टेलीमेडिसिन, डीप-टेक, मेड-टेक, हेल्थ-टेक और क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में सहभागी बनें, अपने सुझाव दें, सरकार उन्हें अंगीकार करेगी और लागू भी करेगी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी विश्वास के साथ प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सैनी, राज्यसभा सदस्य एवं रामकी ग्रुप के फाउंडर अयोध्या रामी रेड्डी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप सांघवी, जाइडस लाइफ साइंसेज के चेयरमैन पंकज पटेल, मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन रमेश जुनेजा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के चेयरमैन सतीश रेड्डी, टोरेंट फार्मा के वाइस चेयरमैन जीनल मेहता, एमएसएन लैब के चेयरमैन एमएनएस रेड्डी तथा संदीप जैन, वी कृष्ण मोहन, आदित्य वर्मा, अमिताभ दुबे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर में बनेगा वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब: जेपी नड्डा

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला प्रमुख राज्य बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस उद्यमिता और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक है। ललितपुर में विकसित हो रहा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क और राज्य की फार्मास्यूटिकल नीति-2023, उत्तर प्रदेश को विश्वसनीय मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, कुशल मानव संसाधन और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण के कारण यूपी फार्मा निवेश का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। केंद्र की नीतिगत दृष्टि और उत्तर प्रदेश सरकार के जमीनी प्रयास प्रदेश को फार्मा और बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है केंद्रीय बजट: पंकज चौधरी

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 01 फरवरी को प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत-2047 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक सशक्त और दूरदर्शी विजन डॉक्यूमेंट है।

पंकज चौधरी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने आमजन की सुविधाओं, नवाचार, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और समावेशी विकास पर निरंतर फोकस किया है। इसी सोच का स्पष्ट प्रतिबिंब बजट 2026-27 में देखने को मिलता है, जो किसान, युवा, महिला, उद्यमी और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आधारभूत संरचना को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए इसके लिए अब तक का सबसे निरंतर और मजबूत निवेश किया है।

वर्ष 2014-15 में जहां इन्फ्रा बजट मात्र 2 लाख करोड़ रुपये था, वहीं इसे चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर अब 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। पंकज चौधरी ने कहा कि बजट में देश को सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात दी गई है, जिनमें दिल्ली-वाराणसी एवं वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को लाभ पहुंचाएंगे। इन परियोजनाओं से नोएडा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को तेज-गति से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रा समय घटेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

इसके साथ ही पूर्व में डांकुनी से पश्चिम में सूरत तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। अगले पांच वर्षों में 20 नए वाटरवेज शुरू किए जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स अधिक किफायती होगी। इसी क्रम में वाराणसी में गंगा जलमार्ग पर जलयान मरम्मत एवं शिप-रिपेयर केंद्र विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। शपंकज चौधरी ने बताया कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित किए जाएंगे, जिन पर अगले पांच वर्षों में प्रति शहर 5000 करोड़ रुपये तक खर्च किए जाएंगे।

होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला इंजीनियर का शव

शाहजहांपुर। जिले में एक होटल के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में एक सिविल इंजीनियर का शव मंगलवार को बरामद किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक होटल के कमरे में गौरव सक्सेना (47) नामक व्यक्ति का शव आज सुबह उनके कमरे से बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गौरव सक्सेना उत्तराखंड के ऋषिकेश के रहने वाले थे और उनका ससुराल शाहजहांपुर में है तथा वह सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के मुताबिक गौरव ने रविवार को होटल में कमरा किराये पर लिया था और तब से यहीं पर रुके हुए थे। पुलिस ने उनके कमरे में शराब की कुछ बोतल भी बरामद की है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है बजट विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं: केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो चुका है। यह बातें मंगलवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से बजट पर वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही।

उन्होंने कहा कि हाई-स्पीड रेल और रेलवे विस्तार के तहत देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कारिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है। इससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों की कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों की तेज होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे - यूपी को लाजिस्टिक हब के लिए बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग, मल्टी माडल लाजिस्टिक और फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। एमएसएमई के क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योग के लिए दस हजार करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए दस हजार करोड़ सरकार ने बजट निर्धारित किया है। इससे उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में पिछड़े और आकांक्षी जिलों पर विशेष फोकस रखा गया है।

जिससे पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उपमुख्यमंत्री केशव ने कहा कि कृषि में एआई और तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता और आय दोनों बढ़ेगी। इसी तरह नेशनल वॉटरवे-1 गंगा नदी पर जहाजों के रख-रखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित होगी। जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 36 जीवनरक्षक दवाओं पर शुल्क छूट, हर जिले में बालिकाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने की योजना की घोषणा की गई है।

जिससे बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेगा। युवा और नई टेक्नोलॉजी, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में काम किया जाएगा। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण की घोषणा से उत्तर प्रदेश के परम्परागत उद्योग को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है,वह क्या करे।

डंपर से कुचल कर बाइक सवार की मौत

कानपुर। चौबेपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्विस रोड पर विपरीत दिशा से जा रहे बाइक सवार युवक की डंपर से कुचलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पड़ताल में जुट गई है। सहायक पुलिस आयुक्त बिल्हौर मंजय सिंह ने मंगलवार को बताया कि यह हादसा ततियागंज इलाके में सर्विस रोड पर उस समय हुआ, जब शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिलहन गांव निवासी ट्रैक्टर चालक रणजीत (32) अपनी बाइक से विपरीत दिशा में कानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर को देखकर उसने बचने के प्रयास में अपनी बाइक कच्ची सड़क की ओर मोड़ दी। कच्ची सड़क पर मिट्टी गीली होने के कारण बाइक फिसल गई और रणजीत संतुलन खो बैठा। वह सड़क पर गिर पड़ा और उसी दौरान डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

न्यायिक कार्य करने के दौरान अधिवक्ताओं का सहयोग अनुकरणीय : न्यायमूर्ति

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। अंतिम कार्य दिवस पर आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाल में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव को विदाई दी गई।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाण्डे, महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और कुबेर का पौधा भेंटकर उनका स्वागत और अभिनन्दन किया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने बार एसोसिएशन के सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुझे अत्यंत सुखद अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनपदों की बार एसोसिएशन से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला था। आज मैं जो कुछ भी हूं, यह आप सभी की वजह से हूं। मैंने यह महसूस किया है कि जनपद न्यायालय अनजाने लोगों का समूह नहीं है, यहां सभी अपने हैं।

उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य सम्पादित करने के दौरान अल्प समय में सम्मानित वरिष्ठ, कनिष्ठ अधिवक्ता से जो प्रेरणा और स्नेह प्राप्त हुआ, वह मेरे लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा।हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पाण्डे बबुआ ने कहा कि न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव अपने निर्णयों से जाने जाते रहे हैं। न्यायिक कार्यों के सम्पादन के दौरान न्यायमूर्ति के चेहरे पर कभी उत्तेजना नहीं देखी गई।

महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने कहा कि न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए, उतना कम है। न्यायिक कार्य सम्पादित करने के दौरान न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को एक समान सुनकर हमेशा निर्णय पारित किया। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति की यादें हमेशा अधिवक्ताओं के हृदय में रहेगी।

भाजपा सरकार किसान विरोधी : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों को लाने को किसान विरोध बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि भारत के बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों व खाद्यान्नों के लिए खोल देना, हमारे देश की खेती-किसानी पर रोज़ी-बसर करने वाली 70 ऊ% आबादी के साथ धोखा है।

भाजपाई और उनके संगी-साथी आज़ादी से पहले भी विदेशियों के एजेंट थे, आज भी हैं। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात करनेवाले भाजपाई और उनके संगी-साथी जनता के बीच जाकर बताएं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ धोखा करने के लिए कितना कमीशन खाया है। इससे केवल किसान ही नहीं, निम्न मध्यवर्ग और मध्यम वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित होगा क्योंकि इससे खाद्यान्न और कृषि उत्पादों की मुनाफ़ाखोरी व बिचौलियों की एक नयी जमात पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से खाने-पीने की सब चीज़ें और भी महंगी हो जाएंगी। साथ ही भाजपा इन कंपनियों से चंदा वसूली भी करेगी, जिससे खाद्य व कृषि उत्पाद और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे।

इससे धीरे-धीरे हमारे किसानों की खेतीबाड़ी और आय कम हो जाएगी और वो मजबूर होकर अपनी ज़मीन अमीरों व कारपोरेट को बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करना ही भाजपाई और उनके संगी-साथियों का आख़िरी मक़सद है।

रायबरेली में गड्ढे में डूबने से चार साल के बच्चे की मौत

रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में घर के दरवाजे पर खेलते समय चार वर्ष का एक बच्चा गड्ढे में गिर गया, जिससे वह पानी में डूब गया और बाद में उसकी मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना जिले के ऊंचाहार के डिहवा मजरे कंदरावा गांव की है। आस-पास किसी के नहीं होने के कारण बच्चे के गड्ढे में गिरने की जानकारी किसी को नहीं हो सकी। काफी देर तक जब बच्चा नहीं दिखा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई। गड्ढे से बच्चे को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक ऊंचाहार के डिहवा मजरे कंदरावा गांव के रहने वाले उमेश कुमार राजस्थान के एक भट्ठे में काम करते हैं। गांव में उनकी पत्नी शीला अपने तीन बेटे आयुष, अर्पित और आर्यन के साथ रहती हैं। उमेश का चार वर्षीय बेटा आर्यन सोमवार को खेलते समय दरवाजे पर बने चार-पांच फुट गहरे गड्ढे में भरे पानी में गिरकर डूब गया। गड्ढा निजी इंडिया मार्का हैंडपंप लगाने के लिए बनाया गया था। काफी देर तक जब बच्चा नहीं दिखा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बच्चे को गड्ढे से निकालकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऊंचाहार पुलिस के कोतवाल अजय कुमार राय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने बताया कि पानी की समस्या दूर करने के लिए उमेश हैंडपंप लगवाना चाहते थे। दरवाजे पर गड्ढा भी बन गया था, लेकिन किसी कारणवश हैंडपंप नहीं लगा। गड्ढे की भराई भी नहीं कराई गई। उसमें गंदा पानी भर गया था।

शीर्ष अदालत की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के बावजूद उप्र में दंडात्मक ध्वस्तीकरण जारी: उच्च न्यायालय

प्रयागराज। प्रदेश में ध्वस्तीकरण कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के नवंबर, 2024 के 'बुलडोजर न्याय' को अस्वीकार्य बताने वाले निर्णय के बावजूद प्रदेश में ढांचों के खिलाफ दंडात्मक ध्वस्तीकरण जारी है। अदालत ने प्रदेश के हमीरपुर जिले में उस शख्स के रिश्तेदारों की याचिका पर यह टिप्पणी की है जिसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) एवं धर्मांतरण रोधी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

याचिका में वादियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की आशंका जाहिर करते हुए अदालत से संरक्षण की गुहार लगाई गई है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या किसी अपराध के घटित होने के तुरंत बाद किसी संरचना को ध्वस्त करना, कार्यकारी विवेकाधिकार का एक दिखावटी प्रयोग है। अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें अपराध घटित होने के तुरंत बाद संपत्ति के कब्जेदारों को ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी

किए गए और इसके बाद, वैधानिक आवश्यकताएं दिखावटी रूप से पूरी कर आवास स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। अदालत ने मामले की स्व्यापकस्र प्रकृति को ध्यान में रखा है जिसमें किसी संरचना को ध्वस्त करने का राज्य का अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उसमें रहने वाले लोगों के अधिकार शामिल हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी की अगली तारीख तय की।

उच्च न्यायालय ने 21 जनवरी को पारित फैसले में कहा है कि दोनों पक्षों द्वारा प्रारंभिक दलीलें दी गई हैं और याचिकाकर्ताओं के मामले से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता प्राथमिकी में सह-आरोपी नहीं है, फिर भी प्रतिवादी (प्रशासन) ने याचिकाकर्ता संख्या दो को प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद उस आवासीय मकान को लेकर नोटिस जारी किया है जिसमें वे रहते हैं। अदालत ने कहा कि वहीं, याचिकाकर्ता संख्या तीन के नाम दर्ज एक वाणिज्यिक संपत्ति "इंडियन लॉज" को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया और याचिकाकर्ता संख्या दो के नाम दर्ज एक आरा मिल के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया और इसे भी सील कर दिया गया। याचिका में याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि उनकी संपत्तियां बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चिन्हित की गई हैं, इसलिए इन्हें ध्वस्त होने से बचाने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की उच्च न्यायालय से गुहार लगाई गई। तथ्यों के मुताबिक, फैमुद्दीन और अन्य ने यह कहते हुए एक रिट याचिका दायर की है कि उनके रिश्तेदार (अफान खान) के खिलाफ बीएनएस, पॉक्सो अधिनियम, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यद्यपि उक्त प्राथमिकी में वे सह आरोपी नहीं हैं, फिर भी पुलिस की मिलीभगत से भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया और हमीरपुर में स्थित उनकी संपत्तियां अधिकारियों द्वारा ढहाई जा सकती हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने प्रारंभिक आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका समय से पूर्व ही दाखिल कर दी गई और याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देना आवश्यक है। अदालत को मौखिक आश्वासन दिया गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बगैर कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाएगा।

हालांकि, यह देखते हुए कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य में इस तरह के विध्वंस जारी हैं, पीठ ने 21 जनवरी को पारित आदेश में उठाए गए सवालों पर विचार करना उचित समझा। नवंबर 2024 में, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने टिप्पणी की थी कि बुलडोजर के माध्यम से न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय प्रणाली में स्वीकार्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा भारत

हरारे। अब तक खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम बुधवार को यहां आईसीसी अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी। इस प्रतियोगिता के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। उसने पांच बार खिताब जीते हैं।

उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है जिसने चार बार ट्रॉफी जीती है। इस तरह से भारत रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने की दिशा में बुधवार को एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत ने अब तक टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। उसने अपने सभी पांच मैच आसानी से जीते हैं, जिसमें सुपर सिक्स चरण में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पर 58 रन की जीत भी शामिल है। भारतीय टीम हालांकि अफगानिस्तान को कम करके आंकने की गलती नहीं करेगी। अफगानिस्तान का भी टूर्नामेंट में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। उसने अपने पांच मैचों में से चार जीते हैं। उसे एकमात्र हार श्रीलंका से मिली थी। लेकिन खिलाड़ियों की फॉर्म और खेल के हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अब तक पांच मैचों में दो अर्धशतकों की मदद से 199 रन बनाए हैं। बड़े-बड़े शॉट खेलने में माहिर सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (पांच मैचों में दो अर्धशतकों सहित 196 रन) भी अच्छी फॉर्म में हैं, लेकिन टीम प्रबंधन चाहेगा कि वह अपने अर्धशतकों को शतकों में तब्दील करें। ऑलराउंडर विहान मल्होत्रा (पांच मैचों में 172 रन) एक और भारतीय बल्लेबाज हैं जिन पर सभी की नजर रहेगी। उन्होंने ग्रुप चरण में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक (109 नाबाद) लगाया था। कप्तान आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पांच मैचों में अपनी ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी से छह विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने पांच मैचों में सिर्फ 99 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 53 रन है। सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज की फॉर्म भी भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि दाएं हाथ का यह बल्लेबाज तीन पारियों में केवल 46 रन ही बना सका है। भारतीय गेंदबाजी की कमान दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हेनिल पटेल और आरएस अंबरीश के हाथ में है। इन दोनों तेज गेंदबाजों को स्पिनर खिलन पटेल का भी अच्छा सहयोग मिला है, जिन्होंने पांच मैचों में आठ विकेट लिए हैं।

म्हात्रे और मल्होत्रा गेंदबाजी में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। मल्होत्रा ने अभी तक टूर्नामेंट में अपनी ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी से पांच विकेट लेने के अलावा भारत की तरफ से एकमात्र शतक भी लगाया है।

टीम इस प्रकार हैं

- **भारत अंडर-19:** आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उधव मोहन, किशन सिंह।
- **अफगानिस्तान अंडर-19:** महबूब खान (कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, फैसल शिनोजादा, खालिद अहमदजई, उस्मान सादात, उजैरुल्लाह नियाजई, अब्दुल अजीज, अकील खान, खातिर स्टानिकजई, नाजीफुल्लाह अमीरी, नूरिस्तानी उमरजई, रूहुल्लाह अरब, सलाम खान, वहीदुल्लाह जादरान, जैतुल्लाह शाहीन।

मैच दोपहर 1:00 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा

सभी टेस्ट खेलने की इच्छा के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हुआ: पैट कमिंस

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने कहा कि चोटिल होने के कारण टी20 विश्व कप से बाहर होने का उनका फैसला आगामी टेस्ट सत्र के लिए पूरी तरह से फिट होने की इच्छा से भी प्रेरित था, जिसमें वह सभी मैच खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट और वनडे के कप्तान कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण टी20 विश्व कप से बाहर हो गए। उनकी जगह बेन ड्वार्शियस को टीम में शामिल किया गया है। टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू होगा। कमिंस ने 'ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस' से कहा, ''यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं, बस एक मामूली सी परेशानी हुई और उससे उबरने के लिए समय कम पड़ गया। मैं कुछ हफ्तों तक आराम करूंगा और फिर आगे की योजना बनाऊंगा।'' उन्होंने कहा, ''एडिलेड टेस्ट मैच के बाद हमें पता था कि चोट को पूरी तरह से ठीक होने में चार से आठ सप्ताह का समय लगेगा। शुरू में हमें लगा था कि इसमें चार सप्ताह ही लगेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन अभी-अभी एक स्कैन करवाया है और चिकित्सकों का मानना है कि इसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ सप्ताह और लगेंगे। इसलिए समय की थोड़ी कमी पड़ गई।'' ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचों का व्यस्त कार्यक्रम अगस्त से शुरू होगा, जब वह डार्विन और मैकाय में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलेगा। इसके बाद वह सितंबर में टेस्ट और वनडे के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगा और फिर पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर श्रृंखला के लिए भारत का दौरा करेगा। इसके बाद वह अगले साल मार्च में मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने पर गुलाबी गेंद से टेस्ट मैच खेलेगा। इसके बाद इंग्लैंड में एशेज श्रृंखला, वनडे विश्व कप और जून में लॉर्ड्स में विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा। कमिंस ने कहा, ''हमने सोचा कि आगामी सत्र में क्रिकेट मैचों की संख्या को देखते हुए साल के पहले छह महीने में संयम बरतना काफी अच्छा रहेगा। चोट ठीक हो जाएगी और इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अगर मैं अभी इसको लेकर सतर्कता नहीं बरतता तो समस्या बढ़ सकती थी।'' कमिंस को हालांकि उम्मीद है कि वह 26 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करने के लिए समय पर फिट हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ''हम चोट की स्थिति के आधार पर ही निर्णय लेंगे। कुछ सप्ताह बाद एक और स्कैन होगा और अगर रिपोर्ट अच्छी रही तो हम धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या में सुधार करेंगे। टेस्ट मैचों की तुलना में टी20 मैचों के लिए तैयारी करना थोड़ा आसान होता है।''

भारत करेगा निशानेबाजी की एशियाई ओलंपिक क्वालीफाइंग चैंपियनशिप की मेजबानी

नई दिल्ली। भारत अगले साल एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप (राइफल/ पिस्टल) की मेजबानी करेगा, जिसमें 2028 में लॉस एंजिल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान दांव पर लगे होंगे। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) के अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव को लिखे पत्र में इसकी पुष्टि की। एनआरएआई ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली में होगा और इसकी तिथियों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एशियाई निशानेबाजी परिसंघ ने पत्र में कहा कि हम भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को एशियाई राइफल/ पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी हासिल करने पर बधाई देते हैं, जहां लॉस एंजिल्स में 2028 में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए आठ कोटा स्थान वितरित किए जाएंगे।'' एक पत्र में कहा गया है कि हमें पूरा विश्वास है कि आपके (एनआरएआई) नेतृत्व में चैंपियनशिप का आयोजन उच्चतम मानकों के अनुरूप होगा और यह एक सफल प्रतियोगिता साबित होगी।

विश्व चैंपियन गुकेश मई में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में खेलेंगे

ओस्लो। मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश मई में यहां नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे जिसमें दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और गत चैंपियन मैग्नस कार्लसन सहित कई स्टार खिलाड़ी शिरकत करेंगे। गुकेश ने 25 मई से पांच जून तक होने वाले इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी है। यह दुनिया के सबसे कड़े शतरंज टूर्नामेंट में से एक होगा।

यह प्रतियोगिता अपने पारंपरिक स्थल स्टेवेंगर से ओस्लो में स्थानांतरित होने वाली है। पिछले साल ओपन वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे भारतीय स्टार गुकेश खेल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन के रूप में ओस्लो आएंगे। गुकेश ने एक विज्ञप्ति में कहा, ''मैं नॉर्वे शतरंज में फिर से हिस्सा लेकर बहुत खुश हूं। हमेशा की तरह बहुत मजबूत खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला करूंगा और सभी रोमांचक

बाजियों का इंतजार कर रहा हूं।'' गुकेश ने 2024 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और फिर तत्कालीन विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर सिर्फ 18 साल की उम्र में विश्व खिताब हासिल किया। गुकेश ने अपनी प्रगति के दौरान कई उपलब्धियां हासिल की जिसमें 2750 रेटिंग अंक पार करने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी बनना और 12 साल की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करना शामिल है। वह शतरंज के इतिहास में तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर हैं। नॉर्वे शतरंज में 2025 में गुकेश ने कार्लसन पर अपनी पहली क्लासिकल जीत भी हासिल की थी। कार्लसन ने पिछले महीने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की पुष्टि की थी। सभी प्रारूप में 20 बार के विश्व चैंपियन ने पिछले 13 वर्षों में हमेशा अपने घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हालांकि उन्होंने धीरे-धीरे क्लासिकल शतरंज से दूर होने की इच्छा जताई थी। नॉर्वे शतरंज एक क्लासिकल प्रारूप की प्रतियोगिता है और मौजूदा विश्व रैपिड और ब्लिट्ज़ चैंपियन कार्लसन ने इसे सात बार जीता है। एक अन्य भारतीय स्टार आर प्रज्ञानानंदा ने भी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है।

भारतीय ग्रैंडमास्टर और विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख नॉर्वे शतरंज में महिलाओं के वर्ग में पदार्पण करेंगी और 2024 में इस वर्ग के शुरू होने के बाद महिलाओं के टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन जाएंगी। अब तक किसी भी भारतीय ने यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट नहीं जीता है।

हार के बावजूद सबालेंका शीर्ष पर बरकरार नोवाक जोकोविच तीसरे स्थान पर पहुंचे

मेलबर्न। कार्लोस अल्काराज़ से ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में हारने वाले 24 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन नोवाक जोकोविच नवीनतम विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अल्काराज़ ने दूसरे नंबर के खिलाड़ी यानिक सिनर से आगे रहते हुए एटीपी टूर पर अपनी नंबर एक रैंकिंग बरकरार रखी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में सिनर को हराने वाले जोकोविच एक पायदान ऊपर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 38 वर्षीय जोकोविच अगस्त 2024 के बाद पहली बार शीर्ष तीन में शामिल हुए हैं। डब्ल्यूटीए टूर पर एरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में एलिना रयबाकिना से हारने के बावजूद अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है। रयबाकिना रैंकिंग में दो स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गईं, जबकि इगा स्वियातेक दूसरे स्थान पर हैं। डब्ल्यूटीए रैंकिंग में चौथे से छठे स्थान पर तीन अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा, कोको गॉफ और जेसिका पेगुला हैं। सेमीफाइनल में हारने वाली एलिना स्वितोलिना दो पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गईं हैं।

कारोबार

संक्षिप्त खबरें

शुल्क कटौती से अमेरिका को भारतीय निर्यात में तेजी आएगी: निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए उच्च अमेरिकी शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि इससे अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात को और प्रोत्साहन मिलेगा। सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात पर 18 प्रतिशत का घटा हुआ शुल्क लागू होना भारत के लिए एक 'शुभ संकेत' है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बनी सहमति के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस समझौते की घोषणा की थी। हालांकि, समझौते के विस्तृत विवरण का अभी इंतजार है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए बाजारों तक पहुंच और इस शुल्क कटौती को मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत का निर्यात बढ़ेगा। उन्होंने कहा, ''इन दोनों को एक साथ रखकर देखें तो अब निर्यात में तेजी आएगी।'' अमेरिका ने अगस्त में भारतीय उत्पादों के आयात पर शुल्क को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के अलावा रूस से तेल खरीद जारी रखने पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया था। इस तरह भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क लग रहा था।

वायदा कारोबार में तीन दिन की गिरावट के बाद चांदी, सोने में जोरदार उछाल

नई दिल्ली। घरेलू बाजारों में तीन दिन की गिरावट के बाद निवेशकों की लिवाली बढ़ने के कारण मंगलवार को वायदा कारोबार में चांदी और सोने की कीमतों में जोरदार उछाल आया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में, मार्च डिलिवरी वाली चांदी की कीमत 29,372 रुपये, या 12.43 प्रतिशत बढ़कर 2,65,633 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। चांदी 2,70,398 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, जिसमें 34,137 रुपये, या 14.4 प्रतिशत की बढ़त हुई। सोमवार को यह 2,36,261 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। यह उछाल एक बड़ी बिकवाली के बाद आया, जिसमें शुक्रवार से सोमवार तक चांदी में 41 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे 1,63,632 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई और निवेशकों की काफी संपत्ति खत्म हो गई। यह गिरावट 29 जनवरी को चांदी के 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आई। पिछले तीन सत्रों में भारी गिरावट के बाद सोने की कीमतों में भी जोरदार सुधार देखा गया। सोने के अप्रैल अनुबंध की कीमत मंगलवार को 7,923 रुपये, या 5.5 प्रतिशत बढ़कर 1,51,914 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी। पिछले तीन सत्रों में, सोना 29 जनवरी के 1,83,962 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से लगभग 40,000 रुपये, या 22 प्रतिशत गिर गया था।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का शेयर बाजार ने मनाया जश्न, सेंसेक्स 2,073 अंक चढ़ा

मुंबई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनने की घोषणा से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को जबर्दस्त उछाल दर्ज हुआ। मानक सूचकांक सेंसेक्स 2,073 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी ने 639 अंक की छलांग लगाई। व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25 प्रतिशत जवाबी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमत हो गया है। इसके अलावा रूसी तेल खरीद जारी रखने पर अमेरिका ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया था। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स कारोबारी सत्र की शुरुआत के बाद 4,205.27 अंक यानी 5.14 प्रतिशत उछलकर 85,871.73 अंक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया।

हालांकि, बाद में मुनाफावसूली होने से यह 2,072.67 अंक यानी 2.54 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,739.13 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 639.15 अंक यानी 2.55 प्रतिशत चढ़कर 25,727.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,252.80 अंक यानी 4.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 26,341.20 अंक तक पहुंच गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी से फोन पर बातचीत के बाद कहा था कि भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा। हालांकि, अभी समझौते का विवरण सामने नहीं आया है। सेंसेक्स की कंपनियों में अदाणी पोर्ट्स में सर्वाधिक 9.12 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, पावर ग्रिड, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी प्रमुख लाभ में रहीं।

हालांकि, तेजी के इस दौर में टेक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। व्यापार समझौते की खबर से वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, समुद्री खाद्य निर्यात और विशेष उपयोग वाले रसायन क्षेत्रों से जुड़े शेयरों में तेज उछाल देखा गया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और रुपये में मजबूती से विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) के प्रवाह की उम्मीद बढ़ी है। अमेरिकी शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से उभरते बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत हुई है और निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए परिदृश्य बेहतर हुआ है।''

ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर. ने कहा, ''भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा और भारतीय निर्यात पर शुल्क कटौती से भारतीय शेयर बाजार ने हाल के समय की सबसे बड़ी एकदिवसीय बढ़त दर्ज की। खासकर निर्यात-उन्मुख एवं जिंसों से जुड़े क्षेत्रों की अगुवाई में बाजार का दायरा बेहद सकारात्मक रहा।'' पोनमुडी ने कहा कि दिग्गज कंपनियों में चौतरफा तेजी के बीच मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने भी इस तेजी का भरपूर फायदा उठाया।

बीएसई पर सूचीबद्ध 3,304 कंपनियों के शेयर चढ़कर बंद हुए जबकि 981 शेयरों में गिरावट रही और 137 अन्य अपरिवर्तित रहे। क्षेत्रवार सूचकांकों में सेवा खंड ने सर्वाधिक 4.86 प्रतिशत की तेजी दिखाई जबकि रियल्टी खंड में 4.79 प्रतिशत, बिजली खंड में 4.79 प्रतिशत, उपयोगिता खंड में 3.92 प्रतिशत, पूंजीगत उत्पाद खंड में 3.71 प्रतिशत और औद्योगिक खंड में 3.44 प्रतिशत की बढ़त रही। इनके अलावा विवेकाधीन उपभोक्ता, धातु, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवा खंडों में भी तेजी रही। मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, ''बाजार को इस समझौते की घोषणा का लंबे समय से इंतजार था और इसकी घोषणा ने एक बड़ी तेजी का रास्ता तैयार किया। इसके पहले यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार समझौता हुआ था। इस तरह भारतीय उत्पादों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।''

निजी पीएफ ट्रस्ट के लिए आयकर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाएगा बजट प्रस्ताव: ईपीएफओ

नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ ने भविष्य निधि ट्रस्ट के लिए आयकर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में रखे गए प्रस्ताव का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न नियमों को एक-दूसरे के अनुरूप बनाने और तालमेल बिठाने से हितधारकों के हितों को मजबूती मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि बजट 2026-27 में मान्यता-प्राप्त भविष्य निधि (पीएफ) से जुड़े आयकर ढांचे को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों के अनुरूप कर दिया गया है।

बयान के मुताबिक, फिलहाल निजी पीएफ ट्रस्ट को आयकर अधिनियम और ईपीएफ अधिनियम की धारा 17 के तहत छूट की पात्रता में अंतर है। इसके अलावा, आयकर प्रावधानों और ईपीएफओ के तहत अधिसूचित निवेश के तरीके भी अलग हैं, जबकि नियोक्ता के अंशदान की सीमा दोनों कानूनों में समान नहीं है। इन भिन्नताओं से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ती है। मान्यता-प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का नियमन आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची-11 के तहत होता है। नए प्रावधानों के तहत आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत पीएफ की मान्यता केवल उन्हीं ट्रस्ट को मिलेगी जिन्हें ईपीएफ अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट मिली हुई है। धारा 17 के तहत नियोक्ता अपने कर्मचारियों के पीएफ खातों के प्रबंधन और मासिक ईपीएफ रिटर्न दाखिल करने से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निवेश के मोर्चे पर कहा कि निवेश मानदंड अभी मौजूदा ईपीएफ ढांचे और अधीनस्थ विधानों के तहत ही नियंत्रित रहेंगे। साथ ही, सरकारी प्रतिभूतियों में 50 प्रतिशत निवेश की अनिवार्य सीमा को हटा दिया गया है। नियोक्ता के अंशदान के संबंध में कहा गया कि अब यह 7.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की मौद्रिक सीमा के अधीन होगा। इस सीमा से अधिक अंशदान पर परिलाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। ईपीएफओ ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में आयकर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना हितधारकों के हितों को साधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारत- अमेरिका करार में कृषि-डेयरी क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं: गोयल

नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक अच्छे व्यापार करार पर सहमति बनी है और इसमें कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। गोयल ने अमेरिका के साथ हुए समझौते का विवरण दिए बिना कहा कि व्यापार समझौता अंतिम चरण में है और समझौते की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए जल्द ही भारत-अमेरिका का एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर समझौते को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा।

उन्होंने विशेष रूप से, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए हुए कहा कि उनकी सोच नकारात्मक है और वह भारत की प्रगति के विरोधी हैं। गोयल ने कहा कि वह संसद में इस समझौते के बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण ऐसा नहीं कर सके। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री

मोदी ने अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता पूरा कर लिया है और देश उन्हें बधाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत को अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता हासिल हुआ है। गोयल ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता देश के गरीबों, मछुआरों, किसानों और युवाओं के लिए काफी अवसर खोलेगा। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ यह व्यापार समझौता भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। गोयल ने कहा कि समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर जवाबी शुल्क 50% से घटकर 18% हो जाएगा।

आठवें वेतन आयोग को लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं: व्यय सचिव

नई दिल्ली। व्यय सचिव वी वुअलनाम ने मंगलवार को कहा कि आठवें वेतन आयोग ने अपना काम अभी शुरू किया है और यह शुरुआती चरण में है, ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्ज-जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नजर रखना जारी रखेंगे।

वुअलनाम ने कहा, ''बजट में अभी आठवें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका कारण आठवें वेतन आयोग का अभी-अभी गठन हुआ है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''वे सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं। इसलिए यह बिल्कुल शुरुआती दौर है। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा।'' उल्लेखनीय है कि सरकार ने जनवरी में आठवें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के

लिए 18 महीने का समय दिया गया है। आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में वुअलनाम ने कहा, '' कर्ज-जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटा दोनों महत्वपूर्ण है और दोनों आपस में जुड़े हैं।

हमने कहा है कि हम ऋण-जीडीपी अनुपात पर नजर रखेंगे... । लेकिन राजकोषीय घाटा और ऋण-जीडीपी अनुपात आपस में जुड़े हुए है। इसलिए हम राजकोषीय घाटे की गणना भी करते रहेंगे।'' उन्होंने कहा, ''लेकिन कुल मिलाकर हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत कर्ज-जीडीपी अनुपात है। इसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक हम एक प्रतिशत घट-बढ़ के साथ इसे 50 प्रतिशत पर लाएंगे। राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी लगातार नजर रखेंगे।'' सरकार ने कर्ज-जीडीपी अनुपात 2026-27 में 55.6 प्रतिशत रहने का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष 56.1 प्रतिशत है। इंटर्नशिप योजना को लेकर बजट में आवंटन से जुड़े एक सवाल के जवाब में सचिव ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और कहा, ''यह एक बहुत अच्छी योजना है और संभवतः इसमें गति कुछ धीमी हो सकती है।

लेकिन ये कुछ हद तक नवोन्मेषी योजनाएं हैं जिनमें उद्योग भी भागीदार है। हमें उन्हें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए मंत्रालय इसे दुरुस्त कर रहा है और उद्योग जगत और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा, '' मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें तेजी आएगी। लोग इसका लाभ देखेंगे और यह सफल होगी।'' बजट में कुल व्यय में वृद्धि और राजकोषीय घाटे में कमी से जुड़े एक सवाल में जवाब में वुअलनाम ने कहा, ''बजट में जो भी आंकड़े हैं, वे वास्तविक हैं। हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। सबसे पहले, व्यय बजट पक्ष की हमने बहुत सावधानीपूर्वक जांच की है। यह निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है।

बॉक्स ऑफिस पर बदला माहौल

'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' की कमाई गिरी

बॉक्स ऑफिस पर इस समय सनी देओल की युद्ध ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी पकड़ बनाए हुए है, जबकि रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' को कमाई के लिहाज से संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। दोनों फिल्मों ने रिलीज़ वीकेंड पर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही नॉन-हॉलीडे दिन आए, दोनों ही फिल्मों की कमाई के आंकड़ों में तेज गिरावट देखी जा रही है, खासकर 'मर्दानी 3' के लिए यह चिंता का विषय बन गया है। सैकनिल्क के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने अपने 11वें दिन (दूसरे सोमवार) बॉक्स ऑफिस पर 6.52 करोड़ रुपये का कारोबार किया। यह आंकड़ा फिल्म के पिछले हफ्ते के वीकेंड वाले कलेक्शंस 9वें दिन 20.17 करोड़ और 10वें दिन 24.22 करोड़ की तुलना में काफी कम है। इसके बावजूद फिल्म ने 11 दिनों में कुल 308.41 करोड़ रुपये कलेक्शन कर लिया है। वहीं 'मर्दानी 3' ने 30 जनवरी को रिलीज़ होने के बाद पहले दिन लगभग 4 करोड़ रुपये की मामूली ओपनिंग की थी। दूसरे दिन इसका कलेक्शन बढ़कर 6.25 करोड़ और तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये रहा। लेकिन सोमवार को फिल्म की कमाई मात्र 2.15 करोड़ रुपये रही। चार दिनों में 'मर्दानी 3' का कुल कलेक्शन 19.65 करोड़ रुपये तक पहुंचा है, जो फिल्म के अनुमानित 60 करोड़ रुपये से ऊपर के बजट को निकालने के लिहाज से संघर्षपूर्ण स्थिति दर्शाता है। दोनों फिल्मों के आंकड़ों से साफ है कि 'बॉर्डर 2' ने नॉन-हॉलीडे के बावजूद बेहतर टैंकिंग जारी रखी है, जबकि 'मर्दानी 3' को दर्शकों के बीच उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।

'धुरंधरः द रिवेंज' का दमदार टीजर रिलीज

खून से सने खौफनाक लुक में दिखे

रणवीर सिंह

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने दुनियाभर में शानदार सफलता हासिल की थी। अब इसके बहुप्रतीक्षित सीक्वल 'धुरंधरः द रिवेंज' को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें रणवीर सिंह खून से सने खौफनाक लुक में नजर आ रहे हैं। जिसने रिलीज से पहले ही फिल्म को सुर्खियों में ला दिया है। करीब 1 मिनट 12 सेकंड लंबे इस टीजर की शुरुआत रणवीर सिंह के इंटेंस अंदाज से होती है। उनका किरदार इस बार पहले से ज्यादा आक्रामक और दृढ़ नजर आ रहा है। टीजर में कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है, बल्कि पहली फिल्म के कुछ प्रभावशाली दृश्यों के जरिए माहौल तैयार किया गया है, जिससे रहस्य और रोमांच बरकरार रहे। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी अपने-अपने किरदारों में वापसी करते दिखाई देंगे। स्टारकास्ट की यह मजबूत मौजूदगी फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रही है। 'धुरंधरः द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में भी रिलीज किया जाएगा, जिससे फिल्म को पैन-इंडिया स्तर पर दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी है।

आदित्य धर मिलाएंगे अल्लू अर्जुन से हाथ, बड़े धमाके की तैयारी

निर्देशक आदित्य धर की हालिया फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंदी सिनेमा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिल्म की सफलता के बाद अब इसका सीक्वल 'धुरंधरः द रिवेंज' रिलीज के लिए तैयार है, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगा। इसी बीच खबर है कि इस सीक्वल के बाद आदित्य अपनी लंबे समय से पेंडिंग एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए वह साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से हाथ मिलाने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, आदित्य धर और अल्लू अर्जुन के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आदित्य ने कुछ साल पहले अल्लू को इस फिल्म की कहानी सुनाई थी और अब एक बार फिर दोनों के बीच इस पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोनों कलाकार इस संभावित सहयोग को लेकर काफी उत्साहित हैं, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा बाकी है। चर्चा है कि यह फिल्म पौराणिक कथाओं से प्रेरित एक भव्य कहानी पर आधारित हो सकती है, जिसे बड़े स्तर पर बनाने की योजना है। माना जा रहा है कि 'धुरंधरः द रिवेंज' की रिलीज के बाद मेकर्स इस नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल अल्लू अर्जुन अपनी आने वाली फिल्मों 'AA23' और 'AA22xA6' को लेकर व्यस्त हैं, लेकिन आदित्य धर के साथ संभावित सहयोग ने पहले से ही फिल्मी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।

विदेश

संक्षिप्त खबरें

नॉर्वे की युवराज्ञी के बेटे ने बलात्कार के आरोपों को स्वीकार नहीं किया

ओस्लो। नॉर्वे की युवराज्ञी (क्राउन प्रिंसेज) के बेटे ने एक अदालत में सुनवाई के दौरान मंगलवार को बलात्कार के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। उनतीस वर्षीय मारियस बोर्ग होइबी, युवराज्ञी मेटे-मारिट के पिछले रिश्ते से सबसे बड़े बेटे और सिंहासन के उत्तराधिकारी युवराज हाकॉन के सौतेले बेटे हैं। होइबी के पास कोई शाही उपाधि या आधिकारिक ड्यूटी नहीं है। अभियोजक स्टर्ला हेनरिकस्बो ने ओस्लो जिला अदालत में होइबी के खिलाफ 38 आरोप पढ़कर सुनाए और उनसे पूछा कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करते हैं। उन्होंने बलात्कार के चार मामलों सहित सभी गंभीर आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आरोपों में एक पूर्व साथी का उत्पीड़न, अन्य के खिलाफ हिंसा और 3.5 किलोग्राम मारिजुआना की तस्करी शामिल है। अन्य आरोपों में जान से मारने की धमकी देना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना शामिल है। हालांकि होइबी ने कई वाहन संबंधी अपराध, एक गंभीर मादक पदार्थ अपराध और एक प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के साथ-साथ धमकी और गंभीर हमले के आरोप को ₹आंशिक रूप सेर स्वीकार किया। अभियोजकों ने कहा है कि अगर होइबी मुकदमे में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। मुकदमे की सुनवाई 19 मार्च तक चल सकती है। सात कथित पीड़ितों के भी गवाही देने की उम्मीद है।

अमेरिकी मध्यस्थता वाली वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूस ने देर रात एक बड़े हमले में यूक्रेन पर लंबी दूरी के लगभग 450 ड्रोन और विभिन्न प्रकार की 70 मिसाइलें दागीं। यह हमला ऐसे समय हुआ, जब दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता से होने वाली वार्ता में भाग लेने वाले हैं, जिसका उद्देश्य लगभग चार साल पहले शुरू हुए युद्ध को समाप्त करना है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के कम से कम पांच क्षेत्रों पर बमबारी का निशाना विशेष रूप से बिजली ग्रिड था। अधिकारियों ने बताया कि रूस के हमलों में कम से कम 10 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, ''रूस के लिए कूटनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण लोगों को आतंकित करना है।'' उन्होंने सहयोगी देशों से अधिक हवाई रक्षा आपूर्ति भेजने और रूस पर ₹अधिकतम दबावर डालने का आग्रह किया ताकि वह 24 फरवरी, 2022 को शुरू हुए युद्ध को समाप्त कर दे। अबू धाबी में वार्ता बुधवार और बृहस्पतिवार को होनी है। रूस ने बिजली संयंत्रों, सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, टर्बाइन और जनरेटर को निशाना बनाकर यूक्रेन के बिजली नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास किया है।

भारत से तेल खरीद रोकने के संबंध में कोई संदेश नहीं मिला है : रूस

मॉस्को। रूस को तेल खरीद रोकने के संबंध में भारत से कोई संदेश नहीं मिला है। रूसी सत्ता के केंद्र 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह बात कही। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ''रूस से तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका तथा संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं।'' 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा, ''हमें इस मामले पर नयी दिल्ली से अभी तक कोई संदेश नहीं मिला है।'' रूसी मीडिया की खबरों के अनुसार, 'क्रेमलिन' के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि रूस हर संभव तरीके से भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखने का इरादा रखता है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि रूस को भारत द्वारा रूसी तेल को अस्वीकार करने की संभावना के संबंध में केवल अमेरिका की ओर से सार्वजनिक बयान ही देखने को मिले हैं। मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे नोवाक ने कहा, ''अभी तो सिर्फ सार्वजनिक बयान ही सामने आए हैं। देखते हैं आगे क्या हालात बनते हैं।'' उन्होंने कहा कि रूस को भरोसा है कि उसके ऊर्जा संसाधनों की वैश्विक स्तर पर मांग बनी रहेगी, क्योंकि वे आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। नोवाक ने कहा, ''कुल मिलाकर, हमारे ऊर्जा संसाधनों की मांग बनी हुई है। आपूर्ति हमेशा मांग के अनुरूप बनी रहेगी क्योंकि संतुलन कायम है।'' रूस के ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि उन्हें भारतीय रिफाइनरी कंपनियों से अनुबंध रद्द करने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। सोमवार को मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत अमेरिका जवाबी शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। पिछले साल ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाए थे, जो दुनिया में किसी भी देश पर सबसे ज्यादा शुल्क था। इनमें रूस से तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत का शुल्क भी शामिल था। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, जिसे पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है। वर्ष 2021 तक भारत द्वारा आयात किए गए कुल कच्चे तेल में रूसी तेल का हिस्सा मुश्किल से 0.2 प्रतिशत था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश भारत, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को से दूरी बनाने के बाद रियायती रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। तेल आपूर्ति पर नजर रखने वाली कंपनी केप्लर के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी के पहले तीन हफ्तों में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात घटकर लगभग 11 लाख बैरल प्रति दिन रह गया, जबकि पिछले महीने यह औसतन 12.1 लाख बैरल प्रति दिन था और 2025 के मध्य में आयात 20 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक होने का अनुमान था। केप्लर के अनुसार, इराक अब रूस के लगभग बराबर मात्रा में आपूर्ति कर रहा है, जो दिसंबर 2025 में औसतन 9,04,000 बैरल प्रति दिन से ज्यादा है। सऊदी अरब से भी तेल का उत्पादन जनवरी में बढ़कर 9,24,000 बैरल प्रति दिन हो गया, जो दिसंबर में 7,10,000 बैरल प्रति दिन और अप्रैल 2025 में 5,39,000 बैरल प्रति दिन के निचले स्तर पर था।

चाइल्ड पोर्न और डीपफेक जांच के संबंध में 'एक्स' के कार्यालयों पर छापेमारी

पेरिस। पेरिस के अभियोजकों ने बाल यौन सामग्री (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) और डीपफेक सहित कई कथित अपराधों की शुरुआती जांच के तहत एलन मस्क के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के फ्रांस स्थित कार्यालयों पर मंगलवार को छापेमारी की। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया कि पिछले साल जनवरी में अभियोजक कार्यालय की साइबर अपराध इकाई ने जांच शुरू की थी। यह इकाई बच्चों को बंधक बनाने और उनकी अश्लील तस्वीरें फैलाने, इससे संबंधित डीपफेक, मानवता के खिलाफ अपराधों और एक संगठित समूह के हिस्से के तौर पर 'ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम' में हेरफेर तथा दूसरे अपराधों में कथित ''मिलीभगत'' की जांच कर रही है। बयान के अनुसार, अभियोजकों ने एलन मस्क और 'एक्स' की 2023 से 2025 तक मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) रहीं लिंडा याकारिनो से स्वैच्छिक पूछताछ के लिए अनुरोध किया है, जिसके लिए 20 अप्रैल की तारीख निर्धारित है। इसमें कहा गया कि अप्रैल में उसी हफ़्ते 'एक्स' के कर्मचारियों को भी गवाह के तौर पर बयान देने के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में 'एक्स' के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध पर तुरंत जवाब नहीं दिया। पेरिस अभियोजक कार्यालय ने 'एक्स' पर जारी छापेमारी की पुष्टि की। इसने कहा कि वह इस मंच को छोड़ रहा है और 'फॉलोअर्स' से भी अपील है कि वे किसी दूसरे सोशल मीडिया मंच से जुड़ें। अभियोजकों ने एक बयान में कहा, ''इस चरण में, जांच एक सकारात्मक सोच पर आधारित है, जिसका मकसद यह पक्का करना है कि 'एक्स' फ्रांसीसी कानून का पालन करे, क्योंकि यह देश की सीमा के अंदर काम करता है।'' यूरोपीय संघ की पुलिस 'यूरोपोल' के प्रवक्ता जान ओप जेन ऊर्थ ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि एजेंसी ''इस मामले में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद कर रही है''। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह जांच सबसे पहले एक फ्रांसीसी सांसद की रिपोर्ट के बाद शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 'एक्स' पर मौजूद पक्षपातपूर्ण एल्गोरिदम द्वारा एक 'ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम' के कामकाज को प्रभावित किए जाने की संभावना है।

परीक्षण के दौरान हुआ ईंधन रिसाव, नासा अब मार्च में अपने चंद्र रॉकेट को प्रक्षेपित करेगा

केप केनरवल (अमेरिका)। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को कहा कि एक दिन पहले किये गए निर्णायक परीक्षण के दौरान ईंधन के रिसाव की समस्या आने के कारण अब वह अपने नये चंद्र रॉकेट को मार्च में प्रक्षेपित करेगी। नासा ने एक बयान में कहा कि प्रक्षेपण में देरी होने से अब उड़ान परीक्षण से पहले डेटा की समीक्षा करने और दूसरा पूर्वाभ्यास करने का मौका मिलेगा। ये रिसाव सोमवार को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में ईंधन भरने की लंबी प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर हुए। नासा ने कहा कि इस उड़ान के लिए चुने गए चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग दो सप्ताह के पृथकवास से बाहर निकाल लिया जाएगा। नासा ने कहा कि चंद्रमा की परिक्रमा के लिए अगली उड़ान के समय से लगभग दो सप्ताह पहले उन्हें फिर से पृथकवास में रखा जाएगा। हालांकि, अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च में आधिकारिक प्रक्षेपण लक्ष्य के बारे में कोई संकेत नहीं दिया। इसने कहा कि ''जांच से प्राप्त डेटा की पूरी तरह से समीक्षा करने, प्रत्येक समस्या का समाधान करने और परीक्षण पर वापस लौटने'' की आवश्यकता है। सोमवार को दोपहर के समय प्रक्षेपण नियंत्रकों ने 322 फुट (98 मीटर) लंबे रॉकेट में अत्यधिक शीतल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भरना शुरू किया। टंकियों में 7 लाख गैलन (26 लाख लीटर) से अधिक ईंधन भरा जाना था। लेकिन रॉकेट के निचले हिस्से में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक हो गई। हाइड्रोजन भरने की प्रक्रिया को कम से कम दो बार रोकना पड़ा क्योंकि प्रक्षेपण दल ने 2022 की पिछले अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली से संबंधित उलटी गिनती के दौरान विकसित तकनीकों का उपयोग करके समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उस उड़ान परीक्षण में हाइड्रोजन रिसाव की समस्या थी और अंततः वह बिना चालक दल के ही उड़ान भरने में सफल रही। नासा ने अपने बयान में यह भी बताया कि परीक्षण के दौरान 'ग्राउंड क्रू' के संचार में ऑडियो में बार-बार रुकावट की समस्या भी आई। इस मिशन के लिए नामित चार अंतरिक्ष यात्रियों - तीन अमेरिकी और एक कनाडाई - ने लगभग 1,000 मील (1,600 किलोमीटर) दूर ह्यूस्टन स्थित जॉनसन अंतरिक्ष केंद्र से महत्वपूर्ण पूर्वाभ्यास की निगरानी की।

नेपाल में एलपीजी की भारी किल्लत, घंटों लाइन में लगने पर भी नहीं मिल रहा सिलेंडर

काठमांडू। नेपाल के एलपीजी उपभोक्ता पिछले दो सप्ताह से रसोई गैस की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं, जिससे घरों और छोटे व्यवसायों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के टैंकर भारत से गैस की आपूर्ति समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इससे पहले मधेशी दलों के नाकाबंदी के दौरान भी काठमांडू समेत देश के विभिन्न हिस्सों में गैस की भारी किल्लत और लंबी कतारें देखने को मिली थीं। प्रतिदिन सैकड़ों एलपीजी उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर काठमांडू के बालाजू औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल गैस कार्यालय पहुंच रहे हैं। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबी कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। नेपाल गैस के कार्यकारी संचालक तथा नेपाल एलपीजी गैस उद्योग संघ के अध्यक्ष गोकुल भंडारी ने बताया कि नेपाल में एलपीजी की दैनिक मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन बाजार में कुछ गड़बड़ी होने के कारण स्थिति को सामान्य होने में कुछ दिन लगेंगे। भंडारी ने बताया कि नेपाल में एलपीजी की प्रतिदिन लगभग 8 हजार सिलेंडर की खपत होती है, जो सर्दियों के महीनों में और बढ़ जाती है। उन्होंने दावा किया कि हाल के दिनों में जितनी मांग है, उससे अधिक गैस बाजार में उपलब्ध है, इसलिए घबराने की कोई स्थिति नहीं है। नेपाल ऑयल निगम ने नेपाल गैस सहित कुछ अन्य गैस कंपनियों के बाजार में गंभीर कमी की जानकारी होने की बात कही है। निगम के प्रवक्ता मनोज ठाकुर ने बताया कि कमी को जल्द दूर करने के लिए उद्योगपतियों को निर्देश दिए गए हैं। ठाकुर ने कहा, ''नेपाल गैस सहित कुछ कंपनियों में समस्या देखी गई है। पाया गया कि वे भारत से समय पर आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। गैस लाने के लिए उनके अपने परिवहनकर्ता नहीं हैं, जो भी हैं वे भारतीय हैं।